bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2079 युगाब्द 5124 कुल पृष्ठ –32 अंक – 24

वर्तमान कमलज्योति

सुराज की विचार यात्रा
वर्तमान कमल ज्योति

15वीं राष्ट्रपति

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति...

आओ करें भूजल संरक्षण, सुरक्षित होगा जीवन हर क्षण
भूजल सप्ताह
16-22 जुलाई, 2022
के अवसर पर
अटल भूजल योजनान्तर्गत
डिजिटल भूजल रथ
का
फ्लैग ऑफ

हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड स्वागत करता है
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
"श्री योगी आदित्यनाथ जी"
का, जिनके कर कमलों द्वारा आज
स्प्रे ड्राइड पाउडर संयंत्र और वितरण केंद्र
का उदघाटन किया जाएगा।
दिनांक:- 21 जुलाई 2022
समय:- पूर्वाह्न 11:30 से अपराह्न 12:30

PROJECT NAKSHATRA INAUGURATION

SEMINAR
MODI@20
DREAMS... MEET... DELIVERY
Democratically Elected Leader, head of the Govt. Continuously for more than 20 years.
Swatantra Dev Singh (President BJP Uttar Pradesh)
Minister of Jal Shakti, UP Govt.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह

सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार

प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को शत्-शत् नमन!

अमृत महोत्सव की पथगामिनी ...

सम्पादकीय

श्रावण मास की समाप्ति के साथ भाद्रपक्ष की काली धटाओं के बीच बारिश की बूंदों से सराबोर देश अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। भारत की स्वतंत्रता का अमृत वर्ष इस अर्थ में अद्वितीय बन गया है कि, अमृत मंथन की प्रथम कड़ी के रूप में प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति विराजमान हुईं हैं। स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान, तकनीक, कृषि, साहित्य, खेल सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की है, बहुत कुछ पाया है, वहीं समय के साथ साथ बहुत कुछ खोया भी है। पिछले 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने वर्तमान में जरूर कुछ जरूर हासिल कर लिया है, जिसकी तरफ संपूर्ण विश्व आज आकर्षित है।

स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमको यह ध्यान दिला रहा है कि, भारत प्राचीन समय से अपनी हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति का वाहक था जो समस्त वसुधा को एक परिवार की संज्ञा देता रहा है। यह वह भारत रहा है जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। यह संस्कृति हमको इस गौरव का भान कराती है कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो विश्व के लिये प्रेरणास्त्रोत बने और विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता के साथ आगे बढ़ें।

स्वतंत्रता का अर्थ देश में अवकाश के एक दिन से लगाया जाता है लेकिन इस दिन का तात्पर्य है, बंधन मुक्त होना, स्वेच्छा से हर काम को गति देना, भविष्य के विकास तथा नव निर्माण के लिए मापदंड तय करना और जीवन के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करना। स्वतंत्रता हर प्राणी की बुनियादी जरूरत है जो देश के हर नागरिक को शांति का एहसास कराती है। स्वतंत्रता के साथ आचार विचार के बंधन मुक्त होने व अनुसंधान के नए मार्ग खुलते हैं। विचारों में आई क्रांति से नये युग का निर्माण होता है। इसलिये आवश्यकता है स्वतंत्रता की कीमत को जानने की। स्वतत्रता दिवस का अर्थ केवल झण्डा फहराना नहीं है अपितु उस तिरंगे से जुड़ी नीतियों एवं सिद्धांतों का पालन करना भी हमारा नैतिक दायित्व है।

संभवतः तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत ,नए संकल्पों का अमृत एवं आत्मनिर्भरता का अमृत है। देश की 75 वीं वर्षगांठ का मतलब 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियां, 75 पर एक्शन और 75 पर संकल्प शामिल हैं, जो आज़ाद भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की समस्त देशवासियों को प्रेरणा देंगे।

हमको यह मानना चाहिये कि, 75 वर्षों में भारत ने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल एवं तकनीकी क्षेत्र अपनी एक पहचान बनाई है। इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। आंतरिक चुनौतियों एवं सांप्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखते हुए भारत ने अपनी अनेकता में एकता की खासियत एवं धर्मनिरपेक्षता की भावना बरकरार रखी है। भारत लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण है। विरोधी विचारों का सम्मान करना लोकतंत्र को नयी ताकत एवं गति प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार 74.04 प्रतिशत है। स्वतंत्रता के समय यह मात्र 12 प्रतिशत थी देश में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप हमारे खाद्यान्न उत्पाद में चार गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई। संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की हुई है। औद्योगिक क्रांति से भारत काफ़ी आगे बढ़ा है। कोरोना वैश्विक महामारी पर देश अंकुश लगाने में सफल हुआ है। इसके लिए डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ सफाई कर्मी एवं वैक्सीन बनाने में जुटे सभी वैज्ञानिक वंदनीय हैं। इन सभी के साहसिक प्रयासों से भारत 200 करोड़ से अधिक को वैक्सीन लगाने में सफल रहा है और अब अपने नागरिकों को बूसटर डोज देने की ओर देश बढ़ गया है।

शहरों की तरह गांवों में तेजी से परिवर्तित हुआ है। गांवों तक सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं पहुँच चुकी हैं। अब गांवों में भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा की ताकत पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंचा है। देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ा है।महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को देश के दूर–दराज के क्षेत्रों एवं विदेशों से जोड़ने में काफी मदद मिल रही है। देश के अंदर छोटे किसानों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा रहा है। आज 70 से ज्यादा रेल रूटों पर, किसान रेल चल रही है। जिसकी सहायता से छोटे किसान, अपने उत्पाद ट्रांसपोर्टेशन के कम खर्च पर, दूर–दराज के इलाकों में पहुंचा सकते में समर्थ हो गए हैं। स्वामित्व योजना द्वारा गावों में घर की एवं जमीन की, ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। इससे न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं बलकि गांव के लोगों को बैंक से आसानी से लोन की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है।

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत आज स्वावलंबी हो चुका है। अपना लड़ाकू विमान ,सबमरीन एवं गगनयान बना रहा है। देश के पास 21वीं सदी की सक्षमता, रोजगार एवं विकास जैसी जरूरतों को पूरा करने वाली नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' उपलब्ध है। हमने अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सफलता अर्जित की, महामारियों का उन्मूलन किया और आईटी क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। दुनिया में आज भारत चार बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है और इसके पास दनिया के अत्याधुनिक मिसाइल हैं।

इसलिये अपी इस स्वतंत्रता को अगर अक्षुण्ण रखना है तब हम सभी को आज़ादी का असली तात्पर्य समझना होगा। अपनी मर्जी से निर्माण कार्यों को गति प्रदान करना ,प्रगति के नए मापदंड तय करना, सार्वजनिक रूप से विचरण करते हुये अपनी खुशियों का इजहार करना , हर धर्म एवं जाति का सम्मान करना एवं सबको बराबर का हक प्रदान करना और इसके साथ आचरण करना। इसलिये स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर हम भारतवासी आज़ादी का सदुपयोग करें, देश की एकता एवं अखंडता को बनाये रखें। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर शहीदों को कोटिशः नमन करें और उनके मार्गों का अनुसरण करते हुये देश को प्रगति के पथ पर लेकर आगे बढ़े।

akatri.t@gmail.com

जीवन के हित-अहित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना : द्रौपदी मुर्मु

मेरे प्यारे देशवासियो

जोहार ! नमस्कार !

भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है।

मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा–आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ।

आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग, मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगे। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करेगा।

ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी।

और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है।

मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है।

हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थीं, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना है।

इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता दो पटरियों पर आगे बढ़ेगा– सबका प्रयास और सबका कर्तव्य।

भारत के उज्ज्वल भविष्य की नई विकास यात्रा, हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी है।

कल यानि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन, भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम, दोनों का ही प्रतीक है।

मैं आज, देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं।

मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गाँव से शुरू की थी।

मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहां मेरे लिये प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था।

लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी।

मैं जनजातीय समाज से हूँ, और वार्ड कौन्सिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। यह लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है।

ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर–सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है।

राष्ट्रपति के पद तक पहुँचना, मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है।

मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।

और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं।

मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है,

देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है।

मेरे इस निर्वाचन में, पुरानी लीक से हटकर नए रास्तों पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूं कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे।

मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा को निरंतर मजबूत किया है।

देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद से लेकर श्री राम नाथ कोविन्द जी तक, अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है।

संविधान के आलोक में, मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी।

मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक–सांस्कृति क आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरी ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। हमारे स्वाधीनता संग्राम ने एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की थी। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा था जिसने आज़ाद भारत के लिए कितने ही आदर्शों और संभावनाओं को सींचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब आंबेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू, चन्द्रशेखर आज़ाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी।

रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नचियार, रानी गाइदिन्ल्यू और रानी चेन्नम्मा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्ररक्षा और राष्ट्रनिर्माण में नारीशक्ति की भूमिका को नई ऊंचाई दी थी।

संथाल क्रांति, पाइका क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया था। सामाजिक उत्थान एवं देश–प्रेम के लिए 'धरती आबा' भगवान् बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी।

मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देशभर में बनवाए जा रहे हैं। एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्षों में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्व–सम्मति से आगे बढ़ाया है।

विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाजों को अपनाते हुए 'एक भारत – श्रेष्ठ भारत' के निर्माण में सक्रिय हैं। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया ये अमृतकाल भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है।

आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ।

भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाई है।

हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित किए।

कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज़ लगाने का कीर्तिमान बनाया है।

इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है।

भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में, आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए, और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं।

आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G–20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रहा है। इसमें दुनिया के बीस बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियाँ निर्धारित होंगी, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री ऑरोबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था।

कुछ ही दिनों बाद श्री अरबिंदो की 150वीं जन्मजयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है।

श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपना ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं।

जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है।

हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपना ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सच होते देख रहे हैं। Vocal For Local से लेकर Digital India तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिला कर 'औद्योगिक क्रांति फोर पॉइंट ओ' के लिए पूरी तरह तैयार है।

रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्ट–अप्स में, नए–नए इनोवेशन में, दूर–सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई हैं, उससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूं कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हों तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूं कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं।

देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है।

आज जब विश्व sustainable planet की बात कर रहा है तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की sustainable lifestyle की भूमिका और बढ़ जाती है।

मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ ताल–मेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। यही संवेदनशीलता आज वैश्विक अनिवार्यता बन गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है।

मैंने अपने अब तक के जीवन में जन–सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है–

"मो जीवन पछे नर्के पड़ी थाउ, जगत उद्धार हेउ"।

अर्थात, अपने जीवन के हित–अहित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ, मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए, हम सभी एक जुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें।

धन्यवाद!

रेवड़ी कल्चर देश के विकास में बाधक : मोदी

राजकुमार

तेजी से प्रगति की दिशा तय करते हुए उ0प्र0 देश का सर्वाधिक एक्सप्रेस–वे वाला प्रदेश हो गया है विकास के दौर में पिछड़ा बुन्देलखण्ड अब देश प्रदेश में जाने के लिए सुव्यवस्थित मार्गों से जुड़ गया। प्रधानमंत्री ने जालौन में 296 किमी लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि, रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर, उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और लोकार्पण दोनों हमारी सरकार में हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इसी का उदाहरण है। इसका काम अगले साल फरवरी में पूरा होना था, लेकिन ये 7–8 महीने पहले ही सेवा के लिए तैयार है। हम समय की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं, इसके अनगिनत उदाहरण यूपी में ही हैं। काशी में विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण का काम हमारी ही सरकार ने ही शुरू किया और हमारी सरकार ने ही पूरा किया। गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किया और उसका लोकार्पण भी हमारी सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने व बुंदेलखंडवासियों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई प्रदान करने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे का लोकार्पण करेंगे। यूपी सरकार के अनुसार, तय समय से 08 माह पूर्व बने इस एक्सप्रेस–वे से प्रदेश सरकार ने 1,132 करोड़ की बचत की है।

प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि, एक समय में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज यूपी में 35 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं और 14 नए मेडिकल कॉलेज में काम चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बगल में जो स्थान हैं, वहां बहुत सारे किले हैं।यूरोप के बहुत सारे देशों में किले देखने का बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग चलता है। मैं आज योगी जी की सरकार से कहूंगा कि अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप भी इन किलो को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइये।

सीएम योगी से आग्रह करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, इस एक्सप्रेसवे के बगल में जो स्थान हैं, वहां बहुत सारे किले हैं। यूरोप के बहुत सारे देशों में किले देखने का बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग चलता है। मैं आज योगी जी की सरकार से कहूंगा कि अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के

बाद आप भी इन किलो को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइये, और प्रदेश के युवाओं के बीच प्रतियोगिता कराइए कि कौन पहले किले पर चढ़ता है।

पीएम मोदी ने कहा कि, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी तो 3–4 घंटे कम हुई ही है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारतभक्ति बहती है, जहां के बेटे–बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का ये उपहार देते हुए मुझे विशेष खुशी मिल रही है।

पीएम मोदी ने बताया कि, बुंदेलखंड के हर जिले में भी 75 अमृत सरोवर बनाएं जाएंगे। ये जल सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा काम है। उन्होंने बताया कि केन–बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं, इससे बुंदेलखंड के बहुत बड़े हिस्से का जीवन बदलने वाला है। आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हमने देश में अमृत सरोवरों के निर्माण का संकल्प लिया है।

योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित बुन्देलखण्ड 2014 के बाद विकास जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया। जिसके लिए यहा के लोगों ने आजादी के बाद दशकों तक प्रतिक्षा किया यह एक्सप्रेस–वे यहाँ सिर्फ वाहनों को ही गति नहीं देगा बल्कि पूरे बुन्देलखण्ड की औद्योगिक प्रगति होगी। इस लोकार्पण समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप वर्मा शामिल होंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी, रामकेश निषाद, मनोहरलाल मन्नू कोरी, सांसद रामशंकर कठेरिया, अनुराग शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, आरके सिंह पटेल भी मौजूद रहेंगे। आदि नेताओं की उपस्थिति में हजारों क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।

अमृत वर्ष महोत्सव : 1947 से 2022

नूतन आकाश को छूने की अपार संभावना

अरुण कान्त त्रिपाठी

आजादी के 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान, तकनीक, कृषि, साहित्य, खेल सहित समस्त क्षेत्रों में विशेष तरक्की की है, बहुत कुछ पाया है, वहीं समय के साथ–साथ बहुत कुछ खोया भी है। बीते 75 सालों में अपनी आंतरिक समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, जिसकी तरफ आज पूरा विश्व आकर्षित है। इन 75 सालों में भारत ने हर मोर्चे पर देश को विकास किया है। इसीलिये भारत आज दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक बनने की राह पर है।

15 अगस्त 1947, यह वह दिन है जब पूरे देश द्वारा मनाया जाने वाला यह एक दिन और एक संघर्ष के अंत का प्रतीक नहीं था, बल्कि देश के पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। इस वर्ष हम एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 गौरवशाली वर्षों को पूरा कर रहे हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता उसके आर्थिक सामाजिक इतिहास और विकास का सबसे बड़ा मोड़ था। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों द्वारा पूर्व में किए गए विभिन्न हमलों और विमुद्रीकरण के कारण, देश बुरी तरह से गरीब और आर्थिक रूप से ध्वस्त हो गया था।

भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप ने वस्तुओं और तकनीकी सहायता में भारत की उतनी ही मदद कि जितना संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी ने किया था। संभवतः इसीलिये 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद, भारतीय राजनीति के सभी नेता चिंतित थे कि व्यापार और निवेश के माध्यम से विदेशी शासन आर्थिक नियंत्रण के बहाने वापसी कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण न हो सके इसके लिये भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के साथ–साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम आरंभ किया। उस समय पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की पहल थी जो तत्कालीन सोबियत संघ में मौजूद लोगों के साथ तैयार की गई थी। लेकिन इससे भारत को कालांतर में कुद अधिक हासिल नहीं हो पा रहा था। 50 से 60 दशक के मध्य भारत की उन्नति के सभी रास्ते लगभग बंद हो गये थे या यह कहें कि लगभग ठहर से गये थे। जून 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित नेहरू के निधन के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन दिया। उसी समय चीन के साथ युद्ध ने भारत में अनाज की कमी और बढ़ती कीमत को जन्म दिया। तब भारत को कृषि पर ध्यान केंद्रित करने और निजी उद्यमों व विदेशी निवेशों के लिए अनुमति देने की आवश्यकता थी। भारत न उस ओर कदम बढाया फलस्वरूप हरित क्रांति के कारण 1978/79 में 131 मिलियन टन का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ। इसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया। तब विश्व ने पाया कि भारत के पास चाय व रबर और इंजीनियरिंग उत्पादों तथा कृषि वस्तुओं का निर्यात शुरू करने के लिए पूंजी और क्षमता दोनों हैं। इसी बीच ताशकंद में शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया और भारत में सभी संसाधन फिर से रूकने लगे।

अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ़्तार तक बढ़ाया गया जहां से विकास का वैश्विक मार्ग प्रशसत होने लगा।

इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रुपये के अवमूल्यन ने कीमतें बढ़ाई थीं। तब तत्कालीन प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका उद्देश्य बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण को बढ़ाना था। लेकिन 1970 से 1990 के मध्य भारत की उत्तरोत्तर प्रगति सोवियत और अमेरिकी नीतियों का बोझ ढोते–ढोते सिमट गई थी। 1991 में जब पी.वी. नरसिम्हा राव ने प्रधान पद संभाला तब उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया, जिससे भारत की विकास दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगी। लेकन, भारत के विकास का रोडमैप 1998 से आरंभ हुआ जब प्रधानमंत्री पर पर आकर अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की आधारभूत संरचना पर ध्यान देना आरंभ किया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा वहीं गावों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शहर व ग्रामीण अर्थव्वस्था को मजबूत किया गया। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ़्तार तक बढ़ाया गया जहां से विकास का वैश्विक मार्ग प्रशसत होने लगा। अटल जी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। 2000 के दशक में भारत आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ने लगा था। भारत अनाज उत्तपादन में आत्मनिर्भर बन गया था। निर्यात की प्रचुरता होने लगी थी। इसके कारण भारत का विदेश व्यापार फलने फूलने लगा तभी भाजपा सरकार चुनाव हार गई लेकिन उसने भारत के जिस आर्थिक विकास को आरंभ किया था बाद की कांग्रेस सरकारों ने विदेशी दबावों में उनको बदलने का कार्य आरंभ कर दिया। 2010 आने तक भारत की विकास गति पूर्णतः धीमी पड़ गई। भारत के जन–जन के बीच कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के साथ ही देश नये भारत के अभ्युदय की आरे बढ़ चला।

आर्थिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन किया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुवात की। भारत के हर एक नागरिक को बैंक का खाता सुनिश्चित किया। जनकल्याण की दिशा में जन–धन योजना की घोषणा के तहत करोडों लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से उज्ज्वला योजना का आगाज हुआ। सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। देश के हर शख्स को बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। सुदूर ग्रामीण विकास की नीतियों को अमलीजामा पहनाया। आज जीएसटी भारत को उन कुछ देशों में से एक बनाता है जिनके पास कर कानून है जो विभिन्न केंद्रीय और राज्यों के कर कानूनों को एकजुट करता है, सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना की गई है।

भाग्य की रेखाओं की तरह सड़कें तरक्की का रास्ता होती हैं। देश में पहली बार प्रतिदिन 37 किमी नेशनल हाईवे 6 से 12 लेन के बनाये जा रहे। आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को और अधिक किफायती बनाने के लिए **"उड़ान योजना"** अक्टूबर 2016 में शुरू की गई है। 5जी से जहां संचारक्रांति आई वहीं इसरो ने एक साथ 100 से ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड मोदी सरकार के कार्यकाल में ही बनाया है। देश बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से **'मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर'** की और बढ़ चुका है। 2014 और 2021 के बीच बहुत कुछ बदल गया है। लाल फीताशाही पद्धति को बदलते हुए सरकार व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करती हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रहा है।

अक्सर भारत में कुछ राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, एन.जी.ओ. और वामपंथी दावा करते रहे है कि देश में अमीर और अमीर, तो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। पूरा सच कुछ और है? निर्विवाद रूप से हमारे देश में गरीबी अभिशाप है। आज भारत की आबादी 135 करोड़ से अधिक है, उसमें गरीबी की स्थिति को लेकर कई वैश्विक रिपोर्टें आई हैं। अमरीकी थिंक–टैंक ब्रुकिंग्स संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यंत गरीब लोगों की संख्या भारत में घटकर 7.3 करोड़ हो गई है और वर्ष 2022 तक इनकी संख्या और कम हो सकती है। उनका अध्ययन यह भी कहता है कि प्रति मिनट 44 भारतीय अत्यंत गरीबी की श्रेणी से बाहर निकल रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने अपनी हालिया रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप, वर्ष 2005–06 में भारत के 55.1 प्रतिशत लोग गरीबी में थे, जो 2015–16 में घटकर 27.9 प्रतिशत हो गए हैं।

यदि कुछ संतोष करने लायक बात है तो वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से महिलाओं की भागीदारी का लगातार बढना है। चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसा उच्च संवैधानिक पद हो या फिर विदेश और रक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय, इन स्थानों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बोर्ड परीक्षा के परिणामों में लड़कियों ने न केवल सुधार किया है, अपितु पिछले डेढ़–दो दशकों से लड़कों को पछाड़ कर लगातार प्रतिवर्ष प्रथम स्थान भी अर्जित कर रही हैं। एक दशक पहले जहां शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं का योगदान 55 प्रतिशत था, वह आज बढ़कर 68.4 प्रतिशत हो गया है। हर्ष का विषय यह भी है कि बाल–विवाह में गिरावट देखी जा रही है तो देश का लैंगिक अनुपात सुधर रहा है।

देश में आज शिक्षा के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुआ है और गंभीर रोगों के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। निम्न आय और गरीबों के लिए केन्द्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न सरकारों द्वारा सस्ता उपचार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। विश्व में कुछ दशक पहले तक भारत की पहचान राजा–महाराजा, हाथी, घोड़ों और सपेरों के देश के रूप में होती थी, किन्तु अब इसमें व्यापक परिवर्तन आया है। आज हमारा देश दुनिया की सबसे उभरती हुई आर्थिक ताकत के साथ अमरीका, रूस और चीन के बाद विश्व की चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन चुका है। हाल ही में चंद्रयान–2 मिशन की ऐतिहासिक सफलता से पहले इसी वर्ष मार्च में भारत, अंतरिक्ष की निचली कक्षा में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता वाला देश भी बन गया था।

मोदी सरकार ने सबसे एतिहासिक फैसला राम मंदिर निर्माण एवं जम्मू–कश्मीर को लेकर लिया । जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ–साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी हुआ. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद–370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। कश्मीर में अलगाववाद और विद्रोह को चारा मुहैया करना वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा करके सरकार ने आतंकवाद पर भी नकेल कसने का काम किया।

आज विश्व भारत को अग्रणी राष्ट्र एक संभावित महाशक्ति के रूप में देखता है। भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अग्रसर है और एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा है। कुछ चुनौतियों के बीच शुभ संकेत यह है कि हम दुनिया के सर्वाधिक युवा लोकतंत्र हैं। एक औसत भारतीय से पूछिए कि क्या वह पड़ोस के किसी देश–पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या चीन में बसना चाहेगा तो अधिकांश का उत्तर न ही होगा। यही हमारी सफलता और विशेषता है, जिसे हमने गत 75 वर्षों में प्राप्त किया है। अभी हमको सभी क्षेत्रों में और अधिक अच्छा करना है और हम कर रहे हैं। देया को युवा खेलों की दुनिया मे नित नया रिकार्ड गढ रहा है। यह अब बदलता भारत है। यह युवा भारत में नये आकाश को छूने की अपार संभावनाओं के साथ अग्रसर हो रहा हैं।

(लेखक कमल ज्योति के संपादक एवं चुनाव प्रबंधन के प्रदेश संयोजक हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **"आजादी का अमृत महोत्सव"** कार्यक्रम के तहत देशवासियों से **"हर घर तिरंगा"** अभियान में भाग लेने की अपील की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **"तिरंगा दिवस"** के मौके पर ये अपील की। हर घर तिरंगा अभियान का मकसद देश के हरेक नागरिक के दिल में देशभक्ति को बढ़ावा देना है। इस बीच स्वतंत्रता सेनानियों के घरों की पहचान करके **"हर घर तिरंगा"** अभियान के तहत पुलिस बैंड की धुन बजाई जाएगी। छात्रों, एनसीसी कैडेटों और एनएसएस स्वयंसेवकों की प्रभात फेरियां भी निकलेंगी।

13-15 अगस्त हर घर पर तिरंगा फहरायेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए लिखा, 'इस वर्ष, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में प्रदर्शित करें। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा।

इससे पहले, पीएम मोदी ने झंडा दिवस के मौके पर ऐतिहासिक दस्तावेजों को साझा किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'आज 22 जुलाई के दिन का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है। 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे सहित इतिहास से कुछ दिलचस्प बातें शेयर कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा, 'आज, हम उन सभी लोगों के महान साहस और प्रयासों को याद करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था, जब हम औपनिवेशिक शासन से लड़ रहे थे। हम उनके विजन को पूरा करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान के बारे में जानकारी दी और लिखा, 'हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और प्रबल भी करता है. 22 जुलाई 1947 के ही दिन तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आजादी के इस अमृत महोत्सव में 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत की गयी है। इस अभियान से देशभर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराये जाएँगे, जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने का काम करेगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़ें। इससे हमारी युवा पीढ़ी में हम तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ा पाएंगे साथ ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीरों का त्याग उन्हें बता पायेंगे।

उत्तर प्रदेश में तिरंगा अभियान

उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जायेगा। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने बताया कि 1 करोड़ झण्डा कार्यकर्ता खरीद कर लगायेंगा। इसके लिए 3, 4, 5 अगस्त को प्रत्येक बूथ, शक्ति केन्द्रों पर बैठक होगी। 9–10 अगस्त को सभी मण्डल में तिरंगा यात्रा होगा। अभियान संयोजक अमरपाल मौर्य ने बताया कि 11 अगस्त को महापुरूषों की मूर्तियों पर स्वच्छता अभियान 13 अगस्त को प्रभात भेरी तिरंगा ध्वज लेकर भजन, देशभक्ति गीत गाते निकलेगा। 13, 14, 15 अगस्त में हम अपने घरों पर तिरंगा फहरायेंगे। जिसको घर का सबसे छोटा सदस्य फहरायेगा। इस ध्वजारोहण का चित्र खींचकर प्रधानमंत्री जी के लिंक पर अपलोड करना है।

जन आकांक्षा की अभिव्यक्ति

डा0 दिलीप अग्निहोत्री

राष्ट्रपति चुनाव में आमजन की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। फिर भी इस शीर्ष पद को लेकर जिज्ञासा अवश्य रहती है। लेकिन इस बार किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं थी. लोगों ने यह मान लिया था कि चुनाव मात्र औपचारिक है।

परिणाम आने के बाद पूरा देश झूम उठा विशेष कर देशभर में जनजाति समाज, गरीब, वंचित समाज देशभर में सड़कों पर उतरकर मा0 मुर्मु जी का अभिनन्दन स्वागत किया।

राष्ट्रपति चुनाव में इस प्रकार के दृश्य अभूतपूर्व थे। आमजन को इसमें मतदान नहीं करना था। लेकिन उत्साह ऐसा था जैसे लोग मतदान के लिए तैयार है। द्रोपदी मुर्मू ने गरिमा के अनुरूप आचरण किया। पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने किसी पर कोई आक्षेप नहीं किया। विपक्ष और उसके उम्मीदवार के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होने राष्ट्र और समाज हित को ही केंद्र में रखा. उनका आचरण शीर्ष पद की गरिमा के अनुकूल था। जिसमें किसी के प्रति दुर्भावना या पूर्वाग्रह नहीं था। यह बात चुनाव प्रचार के दौरान उनके बयानों से प्रमाणित हुई। उनका कहना था कि देश, यह माटी और परमपिता पिता परमात्मा की सेवा ही मेरा ध्येय है। मेरा यह जीवन अपने देश और समाज की सेवा के लिए है।

पद की गरिमा के अनुरूप उन्होंने दलगत अपने को राजनीति से ऊपर रखा। यह सही है कि उनको राजग ने उम्मीदवार बनाया था। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सभी लोगों से समर्थन की अपील की थी। उन्होंने कहा कि अपने संगठन के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं लेकिन जो संगठन के नहीं हैं, वे भी समर्थन में आगे आये हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर देश की सेवा के लिए तैयार हूं। वस्तुतः राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में जब से द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा मात्र से देश आनंद और उत्साह की लहर दिखाई देने लगी थी। अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें विपक्षी मतदाताओं का भी समर्थन मिला। ईमानदारी और संविधान के प्रति आदर से मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाएंगी।

शिवराजसिंह चौहान ने ठीक कहा कि प्रतिभाओं को खोजने संबन्धी नरेन्द्र मोदी का तरीका अद्भुत है। पहले जो दल सत्ता में रहते थे, उनका दायरा कुछ परिवारों तक ही सीमित रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से पूरे देश से प्रतिभाओं को खोजकर निकालते हैं और उन्हें उपयुक्त जिम्मेदारी देते हैं, वह तरीका अद्भुत है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में जनजातीय समाज की एक योग्य बहन को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का जो अवसर मिला है। उनके प्रति केवल जनजातीय समाज ही नहीं आम जनता में खुशी की लहर है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होते ही देश में जो हलचल मची है, वह पहले

कभी नहीं दिखी। कांग्रेस के अंदर भी ये सवाल उठे कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का विरोध क्यों होना चाहिये। अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें समर्थन मिला।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार एक महान वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बनाकर देश को गौरवान्वित किया था। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक दलित नेता को सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुना। इस बार कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक आदिवासी महिला को यह अवसर मिलेगा लेकिन द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित करने के निर्णय से पूरा देश आनंदित और उत्साहित है। उनका चुनौतीपूर्ण सफर हम सबके लिए और देश के जनजातीय समाज के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। उन्होंने पार्षद,विधायक, मंत्री और राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने अपनी सारी पूजी जनजातीय वर्ग की बच्चियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समर्पित कर दी। भाजपा हमेशा जनजातीय समाज के विकास की पक्षधर रही है।

नरेन्द्र मोदी सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से कार्य कर रहे है। इसमें जनजातीय समाज भी शामिल है। आजादी के पचहत्तर वर्षों के बाद भी किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि जनजातीय समाज का कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इसे नरेन्द्र मोदी ने इस कार्य को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए पच्चीस सालों का रोडमैप बनाया है। राष्ट्रपति के तौर पर अगले पांच वर्षो तक द्रोपदी मुर्मू योगदान होगा। यशवन्त सिन्हा नकारात्मक विचार ले कर चल रहे थे। वह कह रहे थे वर्तमान सरकार लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रही है। इसी प्रकार के बयान विगत आठ वर्षो से विपक्षी नेता दे रहे है। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद यशवन्त सिन्हा से इस स्तर की राजनीति से ऊपर उठने की अपेक्षा थी। लेकिन पूर्वाग्रह से पीड़ित यशवन्त सिन्हा ऐसा नहीं कर सके। द्रोपदी मुर्मू ने सकरात्मक विचार देश के सामने रखे। उन्होने कहा कि हमारा देश मजबूत लोकतंत्र की जननी है जिसकी मजबूती के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। इस समय देश का स्थान पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण होने के साथ ही हमारे प्रति विश्व का दृष्टिकोण बदल रहा है।

हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। हमने देश के समग्र विकास का संकल्प लिया है। प्रकृति की पूजा की प्रक्रिया हम जनजातीय समाज से सीखते हैं। वे सदैव संस्कृति की उपासक होते हैं। हमारी लोक परंपरा ही हमारी पहचान है। आंध्र प्रदेश में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने द्रोपदी मुर्मू का समर्थन किया तेलुगू देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था, कहा कि वे गर्व महसूस कर रहे हैं कि आदिवासी महिला पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होगी। यह देश के लिए गौरव की बात भी होगी और तेलुगू देशम पार्टी उनका पूरा समर्थन करती है। दूसरी ओर यशवन्त सिन्हा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपनी प्राथमिकताएं गिनवा रहे थे। उनका एजेंडा नरेन्द्र मोदी के विरोध पर आधारित था। लग ही नहीं रहा था कि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होने खुद कहा कि नरेन्द्र मोदी की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं।

कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते ही नहीं हैं। इस वक्त संविधान के मूल्यों की रक्षा नहीं हो रही है। बल्कि इस सरकार में संविधान के मूल्यों की अवहेलना की जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग पाएंगे कि संविधान नष्ट हो गया है। संविधान का कोई महत्व नहीं रहा। कहीं भी किसी भी फोरम पर नहीं जा सकते। ऐसा लगता है कि आज कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिल सकता है। वह अनुच्छेद 370 की समाप्ति और नागरिकता संसोधन कानून का विषय अनावश्यक रूप से उठा रहे थे। उन्होने राजनीति के चक्कर में उस पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा,जिसके लिए वह चुनाव लड़ रहे थे। प्रचार के दौरान उनकी नरेन्द्र मोदी के प्रति कुंठा व पूर्वाग्रह प्रदर्शित होता रहा यह बात उनके बयानों से प्रमाणित है।

वह कह रहे थे कि वन नेशन, वन पार्टी और चाइना के कम्युनिस्ट शासकों की तर्ज पर वन लीडर की ओर भारत के लोकतंत्र को ले जाने की कोशिशें हो रही है। लोकतंत्र खतरे में है। शैतानी तरीके से देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। देश विभिन्न स्तर पर खतरों से घिरा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। इस प्रकार यशवन्त सिन्हा देश में भय का माहौल बना रहे थे। इसलिए उनके समर्थन में देश के किसी भी क्षेत्र में उत्साह दिखाई नहीं दिया। देश का जनमानस उन्हें सर्वोच्च पद पर देखना ही नहीं चाहता था।

प्रदश सरकार की उपलब्धियां

शहीदों के घर स्मारक तक पथ निर्माण

उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जनमानस को यातायात की सुविधायें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के पुराने निर्मित मार्गो का रख–रखाव एवं बढ़ते यातायात की आवश्यकता को देखते हुए, अधिक यातायात वाले मार्गों का मानक के अनुसार चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराता है। कुछ अन्य विभागों यथा– ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यूपीडा, गन्ना विभाग, जिला पंचायत, ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य विभाग भी मार्ग निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य करते हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा लखनऊ में समस्त सरकारी भवनों का रख–रखाव एवं नई स्वीकृतियों के सापेक्ष भवन निर्माण का कार्य भी कराया जाता है। अन्य जनपदों में भी सरकारी कालोनियों का रख–रखाव एवं अन्य सरकारी भवनों का रख रखाव किया जाता है।

वर्ष 2012 से 2017 के मध्य 15331 कि0मी0 ग्रामीण मार्गो का निर्माण एवं 16,537 कि0मी0 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया गया था। इसके साथ 591 दीर्घ सेतुओं/लघु सेतुओं का निर्माण किया गया था।

वर्ष 2017 से 2022 के मध्य 20,152 कि0मी0 ग्रामीण मार्गो का निर्माण एवं 17,150 कि0मी0 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया गया था। इसके साथ 186 दीर्घ सेतुओं 72 रेल ऊपरगामी सेतुओं 537 लघु सेतुओं अर्थात् कुल 795 सेतुओं का निर्माण किया गया है।

मा0 योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान दूसरी बार दिनांक 25.03.2022 को सम्भाली गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार सम्भालते ही सभी विभागों को प्रथम 100 दिन की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार 06 माह की कार्य योजना, 01 वर्ष की कार्य योजना, 02 वर्ष की कार्य योजना एवं 05 वर्ष की कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिये गये।

प्रथम 100 दिन में 500 से अधिक ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन 500 सम्पर्क मार्गों में 1126 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है और इस पर 787 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि रोजाना लगभग 05 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि 841 कार्य प्रगति में हैं, जिनकी अवशेष लागत रु0 882 करोड़ है। इन सभी ग्रामीण मार्गों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है। विभाग का यह सतत् प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी इसी गति से निर्माण कार्य में प्रगति प्राप्त करते रहेंगे।

विभाग द्वारा प्रथम 100 दिन में 89 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिसकी लागत रु0 834 करोड़ है। यह भी अवगत कराना है कि 1191 सेतु कार्य प्रगति में हैं, जिनकी अवशेष लागत रु0 3758 करोड़ है। इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक 03 दिन में 01 सेतु पूर्ण करने का लक्ष्य है। दीर्घ सेतुओं का निर्माण उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा किया जाता है। सेतु निगम द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 45 नदी सेतु एवं 20 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे वर्ष 2023–24 में दोगुना करते हुए लगभग 40 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाना लक्षित है।

विभाग द्वारा प्रथम 100 दिन में 511 कि0मी0 मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लागत रु0 1441 करोड़ की लागत के पूर्ण किये गये हैं। रु0 17667 करोड़ लागत के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रगति में हैं। इस प्रकार विभाग द्वारा प्रथम 100 दिन में लगभग 05 किलोमीटर प्रतिदिन की उपलब्धि हासिल की गयी है।

10380 कि0मी0 लम्बाई में सड़क मरम्मत का कार्य एवं 2910 कि0मी0 लम्बाई में सड़क मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। क्षतिगस्त मार्गों के सुधार के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हुए अन्य राज्यों यथा– मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरांखण्ड, बिहार, झारखण्ड के प्रवेश द्वार पर 89 अन्तर्राज्यीय स्वागत द्वारों का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 60 अन्तर्राज्यीय स्वागत द्वारों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। स्वागत द्वारों के बनने से प्रदेशवासियों एवं अन्य प्रदेश से आने वाले पर्यटकों/जनमानस को प्रदेश में हो रहे विकास की पहली झलक मिलेगी।

प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मोर्थ के पी0आई0यू0 एवं लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 नामित एजेन्सी हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गो की संख्या 89 है, जिनकी लम्बाई 11,590 कि0मी0 है। गतवर्ष प्रदेश में एन0एच0ए0आई0 एवं एन0एच0 लो0नि0वि0 द्वारा 1720 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूर्ण किया गया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मार्ग, लो0नि0वि द्वारा गत वर्ष प्रस्तुत 662 कि0मी0 एवं लागत रु0 13,325 करोड़ लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री नितिन गडकरी, मा0 मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से हुई वार्ता के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय मार्ग, लो0नि0वि0 द्वारा 1163 कि0मी0 लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास कराने हेतु डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जायेगी। इस वर्ष कार्यो की स्वीकृति हेतु मंत्रालय द्वारा रू0 15,634 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गयी है।

इसके अतिरिक्त मथुरा वृन्दावन क्षेत्र में बृज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण रु0 2500 करोड़ की लागत से कराया जायेगा, जिसके लिये डी0पी0आर0 कन्सलटेन्ट का चयन हो चुका है और डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

एक लाख से अधिक टी0वी0यू0 वाले समस्त लेविल क्रासिंग पर नए आर0ओ0बी0 का निर्माण केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए शीघ्र ही उत्तर प्रदेष सरकार तथा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच एक MOu- साईन किया जायेगा जिसका अनुमोदन कैबिनेट/मा0 मंत्रीपरिषद द्वारा किया जा चुका है। इस मद में पहले से स्वीकृत धनराषि रू0 117.27 करोड़ की केन्द्रीय सहायता को बढ़ाकर सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने रू0 700 करोड़ करने की घोषणा भी कर दी है। इस तरह आगामी वर्षों में समस्त लेविल क्रासिंग पर नए आर0ओ0बी0 निर्माण कराए जाने लक्षित हैं।

विभाग में पारदर्षिता लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसमें से ऑनलाइन एस्टीमेटर दिनांक 23.06.2022 को लांच किया गया है। ऑनलाइन एस्टीमेटर लांच किए जाने से समय एवं कागज की बचत होगी, सभी आगणनों में एकरूपता आएगी तथा समय से कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो सकेंगी।

मार्गों की अनुरक्षण नीति (Maintenance Policy) में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत नव निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (Widening & Strengthening) के कार्यों के अनुबन्ध (Contract) के साथ ही पंचवर्षीय अनुरक्षण नीति (5 years maintenance policy) लायी जा रही है जिससे मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा एवं मार्गों के जल्दी क्षतिग्रस्त होने के कारण आम जनता को हो रही परेशानी से निजात मिलेगी। इसके साथ–साथ अनुरक्षण पर आने वाला व्यय भी सीमित हो सकेगा। इसके अतिरिक्त मार्गों के अनुरक्षण हेतु पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुल 18 मंडलों में से, प्रत्येक मण्डल में एक ब्लॉक की लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की समस्त सड़कों, ग्रामीण मार्ग सहित को पांच वर्ष के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके सफल होने पर पूरे प्रदेष में इसी प्रकार अनुरक्षण कराए जाने पर विचार किया जाएगा।

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 50 करोड़ से अधिक लागत के भवनों के निर्माण का कार्य ई0पी0सी0 मोड पर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को मार्ग कार्यो पर भी लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिसमें ज्यादा अनुभवी ठेकेदार जिनके पास अधिक मात्रा में तकनीकी स्टॉफ एवं मषीनरी उपलब्ध होती है जिससे कार्यो की गुणवत्ता बेहतर रहेगी एवं कार्य भी जल्दी पूर्ण किए जा सकेंगे।

विभागीय गतिविधियों से आम जनमानस को जोड़ने तथा विभागीय विकास कार्यों को आम जनमानस के संज्ञान में लाने से विभागीय छवि को निखारने/अच्छा करने हेतु सोशल मीडिया एजेंसी की सेवा ली जाएगी एवं विभाग के शिकायत प्राणली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के दृष्टिगत सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पिछले वर्षों में 70 नए राज्य मार्ग घोषित किए गए हैं इन समस्त राज्य मार्गों को दो लेन तक चौड़ा किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त समस्त प्रमुख जिला मार्गों को भी दो लेन चौड़ा किए जाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

2011 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों/बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में 4393 बसावटें पक्के मार्ग से नहीं जुड़ी हैं जिनमें से 1087 बसावटों, जिनकी लम्बाई 500 मी0 से कम है को पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जोड़ा जाना प्रस्तावित है एवं शेष समस्त ग्रामों को लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

विगत वर्षों में अभिनव प्रयोग करते हुए विभाग द्वारा 193 मार्गों पर 40,000 हर्बल पौधारोपण का कार्य किया गया है। सिंगिल यूज वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए मार्गों के नवीनीकरण का कार्य कराया गया है। भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु इस प्रकार के कार्य विभाग कराता रहेगा।

आजादी के अमृत महोत्सव के श्रृंखला में शहीद स्मारकों एवं शहीदों के घर तक मार्ग निर्माण का निर्णय लिया गया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्ग दर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझते हुए इसका निर्वहन करने में सफल होगा।

प्रदश सरकार की उपलब्धियां

पारिवारिक सौहार्द: सहज सम्पत्ति हस्तांतरण

प्रदेश के स्टांप तथा पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल ने आज विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना तथा उपलब्धियों पर लोक भवन में स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि विभाग ने 100 दिनों में पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने, रोजगार सृजन, ऑनलाइन सुविधाओं से बढ़ी पारदर्शिता, टोकन डिस्प्ले सिस्टम तथा समग्र विभागीय कार्यों से इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश उन्नति प्राप्त कर रहा है।

अभी तक जन सामान्य द्वारा अपने रक्त सम्बन्धों में नैसर्गिक प्रेम के कारण पंजीकृत कराये जा रहे दानपत्रों पर भी कलेक्टर सर्किल रेट से आगणित बाजार मूल्य पर बैनामा विलेख के समान स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने के प्रावधान थे। विभाग द्वारा 100 दिन की कार्य योजना में लिए गये संकल्प के अनुसार रक्त एवं वैवाहिक सम्बन्धी दानपत्रों में स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान कर दी गयी है। वर्तमान में दानपत्र पर दिनांक 18 जून 2022 को शासनादेश जारी करते हुए अधिकतम 5000,रु० का स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है। उपरोक्त निर्णय को जन सामान्य द्वारा हर्षोल्लास से स्वीकार किया गया है। अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मात्र 20 दिवसों में सम्पूर्ण प्रदेश के अन्तर्गत 15023 रक्त सम्बन्धी दान विलेखों का पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि पूर्व में प्रति माह लगभग 5000 दानपत्रों का पंजीकरण किया जा रहा था।

पूर्व में छोटे मूल्य के स्टाम्प पत्रों को प्राप्त करने के लिए स्टाम्प वेण्डरों के पास जाना पड़ता था जो तहसील अथवा अन्य दूरस्थ स्थान पर उपलब्ध होते थे। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार द्वारा जन सामान्य को विभिन्न कार्यों में छोटे मूल्य के स्टाम्प पत्रों को सुगमता से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विभाग द्वारा ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर, उचित दर विक्रेता (सरकारी राशन विक्रेता, कोटेदार) के माध्यम से छोटे मूल्य के ई–स्टाम्प पत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। शासन के उपरोक्त निर्णय से प्रदेश में छोटे मूल्य के ई–स्टाम्प पत्र आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो रहे है। नगरों में स्थित उप निबन्धक कार्यालयों में असमान क्षेत्राधिकार होने के कारण एक कार्यालय में बहुत बड़ी मात्रा में लेखपत्र पंजीकरण हेतु प्रस्तुत हो रहे थे। वही दूसरे कार्यालय में औसत से बहुत कम मात्रा में लेखपत्र प्रस्तुत हो रहे थे। उपरोक्त व्यवस्था से अत्यधिक लेखपत्रों के प्रस्तुत होने से संबंधित कार्यालय में पक्षकारों की अधिक भीड़ एकत्र होती थी और विलम्ब होता था। सरकार द्वारा उपनिबन्धक कार्यालयों में लागू किये गये समवर्ती क्षेत्राधिकार (Concurrent Jurisdication) को सृजित करने से लेखपत्रों के प्रस्तुतीकरण का कार्य समानुपातिक रूप से होना सम्भव हुआ है। वर्तमान व्यवस्था से सभी उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकरण का कार्य समान होने से लेखपत्रों का गुणवत्ता पूर्ण परीक्षण सम्भव हुआ है तथा लोगों को भी प्रतीक्षा करने से मुक्ति

मिल रही है। सरकार द्वारा प्रदेश के 18 जनपदों में स्थित 19 उप निबन्धक कार्यालयों के समूह में उपरोक्त व्यवस्था लागू की जा रही है।

उपनिबन्धक कार्यालयों में लेखपत्रों के पंजीकरण हेतु एक पटल पर एक साथ कई पक्षकार उपस्थित हो जाते थे जिससे एक समय में एक पटल पर अत्यधिक भीड़ एकत्र हो जाने सेपंजीकरण की प्रक्रिया अव्यवस्थित हो जाती थी तथा जनसामान्य को भी असुविधा का सामना करना पड़ता था। सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए प्रत्येक उपनिबन्धक कार्यालय में 'टोकन डिस्प्ले सिस्टम' स्थापित कराये गये हैं। उपरोक्त व्यवस्था से पक्षकारों को एक स्थान पर बैठकर अपने कम की सूचना मिल जाती है जिससे उनके लेखपत्र के पंजीकरण का कार्य सरलता सहजता एवं पूर्ण पारदर्शिता से सम्पन्न हो रहा है। इससे जनसामान्य को सुविध हुई है तथा शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु अच्छा वातावरण प्राप्त हो रहा है।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग द्वारा 100 दिन में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के संकल्प के अनुसार प्रदेश के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में पारदर्शिता के दृष्टिगत सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित कराये गये हैं। उपरोक्त व्यवस्था से फील्ड स्तर के कार्मिकों के कार्य, आचरण तथा आम जनता के प्रति उनके व्यवहार पर निगाह रखा जाना आसान हुआ है। जनसामान्य को असुविधा पहुँचाने तथा कार्यालय कार्य में बाधा पहुँचाने वाले अराजक तत्वों पर भी निगाह रखी जा सकेगी। उप निबन्धक कार्यालयों में स्थापित सी०सी०टी०वी० फुटेज का अनुश्रवण जनपद स्तर पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा किया जा रहा है। सम्पूर्ण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु मुख्यालय स्तर पर स्टेट कमाण्ड सेंटर स्थापित किया गया है। सम्पूर्ण व्यवस्था से निबन्धन विभाग में सुचिता स्थापित हो रही है।

जायसवाल जी ने कहा कि पक्षकारों के द्वारा अप्रयुक्त, बिगड़े हुए स्टाम्प पत्रों की वापसी एवं उनमें निहित धनराशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में साफ्टवेयर के माध्यम से ओ०टी०पी० आधारित स्टाम्प पत्र में निहित मूल्य की वापसी हेतु सरल व्यवस्था लागू की गयी है। जिससे सम्बन्धित पक्षकार अपने स्टाम्प पत्रों में निहित मूल्य, धनराशि की प्राप्ति ऑनलाइन आवेदन करते हुए अपने खाते में स्वयं प्राप्त कर रहे हैं।

"सेवा सुशासन में निखरता उत्तर प्रदेश"

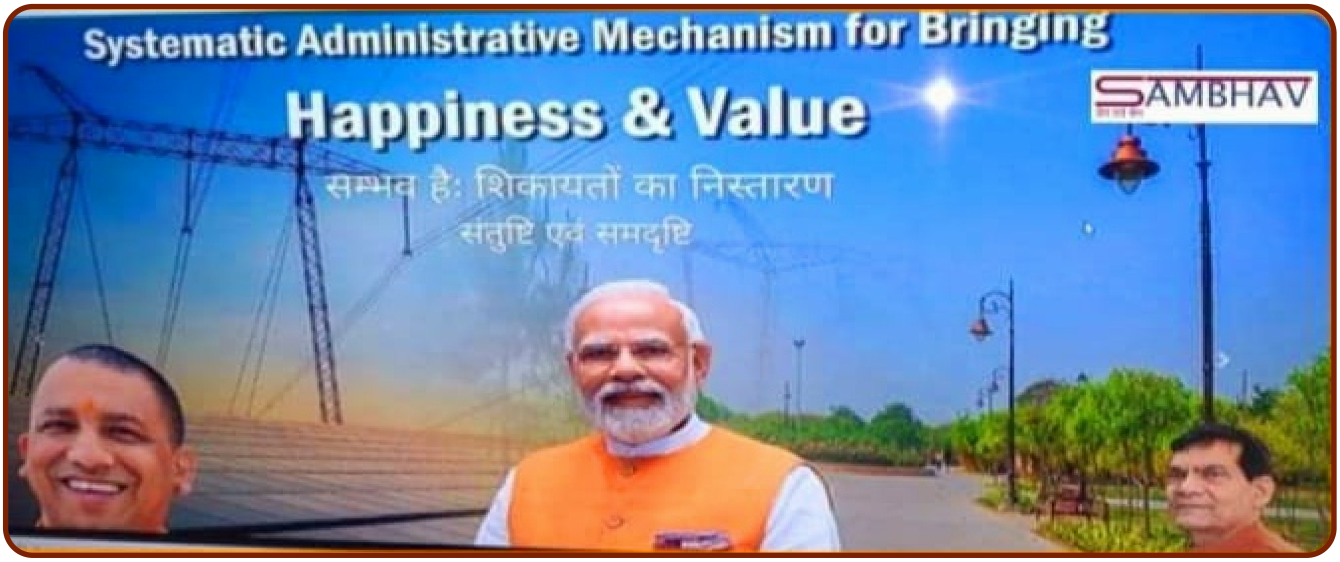

मा0 प्रधानमंत्री जी के सुशासन के 08 वर्ष एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के सुशासन के 05 वर्ष की बदौलत जनता ने केन्द्र एवं राज्य में लगातार दूसरी बार सेवा का अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सेवा एवं सुशासन के 100 दिन पूरे किये हैं।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को 100 दिन, 06 माह, 01 साल, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष के कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके तहत ऊर्जा विभाग के 100 दिन के कार्यों के लक्ष्य को हमने निर्धारित अवधि में ही शत–प्रतिशत पूरा कर लिया है और प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और सुचारू एवं सुदृढ़ करने के विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार दिन–रात मेहनत कर रहे हैं और बेहतर विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के विजन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल व दिशा–निर्देशन में प्रदेष सरकार के सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के संकल्प के साथ ऊर्जा विभाग ने प्रदेष की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु विद्युत उत्पादन, वितरण, ट्रांसमिशन एवं अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में युद्धस्तर पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोबारा सरकार बनते ही प्रचण्ड गर्मी शुरू हो गई थी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार 11 जुलाई 2022 को सर्वाधिक डिमांड 26504 मे0वा0 की आपूर्ति सुनिष्चित कर ऐतिहासिक रिकार्ड बनाया गया तथा 08 जुलाई 2022 को 01 दिवस में सर्वाधिक 541 मि0यू0 विद्युत आपूर्ति की गयी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक की यह सर्वोच्च डिमाण्ड थी, जिसको पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यहीं तक नहीं इस वर्ष हमारी जो न्यूनतम डिमाण्ड थी वह भी पिछले वर्ष 5662 मे0वा0 की तीन गुनी 17669 मे0वा0 थी। सरकार बनने के बाद ही बेहतर अनुरक्षण कार्य पर सर्वाधिक ध्यान ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता में लाकर वर्ष 2021–22 के सापेक्ष इस वर्ष ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता 2.80 प्रतिशत में कमी कर 2.77 प्रतिशत पर लाया गया। जर्जर लाइनों व खराब ट्रांसफार्मर को ठीक कर भीषण गर्मी में भी सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की गई। उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पावर कारपोरेषन के टोल फ्री हेल्प लाइन 1912 में आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के लिए इसकी तकनीकी एवं क्षमता में सुधार करते हुए इस वर्ष में 92.50 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए तकनीक के माध्यम से उपभोक्ता सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए पहली बार 'सम्भव' पोर्टल की शुरूआत कर स्थानीय स्तर पर ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और स्वयं ऊर्जा मंत्री द्वारा भी सुनवाई की जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु एकमुष्त समाधान योजना चलायी गयी, जिसमें सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए बकाये के सरचार्ज पर शत–प्रतिशत छूट दी गई। अभी तक इस योजना से 35.31 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ प्राप्त किया, जिसके अन्तर्गत 2636 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है तथा 761 करोड़ रूपये की राशि सरचार्ज के रूप में मांफ की गयी।

ऊर्जा विभाग ने राजस्व वसूली में भी वर्ष 2022–23 के प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष 2021–22 के प्रथम तिमाही के सापेक्ष राजस्व वसूली में ऐतिहासिक वृद्धि हुयी है। 2021–22 के प्रथम तिमाही में 9419.92 करोड़ राजस्व वसूली हुयी थी। जबकि 2022–23 प्रथम तिमाही में 13763.34 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली हुयी जोकि 46.11 प्रतिशत अधिक है। विभाग ने कभी भुगतान न करने वाले (Never Paid) उपभोक्ताओं से सम्पर्क कर उन्हें भुगतान हेतु प्रेरित करते हुये 1411921

उपभोक्ताओं भुगतान जमा कराया। विद्युत आपूर्ति की बढ़ी हुयी मांग की पूर्ति के लिए गत वर्षों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की इकाईयों को सर्वाधिक कोयला आपूर्ति सुनिष्चित किया गया। अप्रैल एवं जून 2019 में लगभग 52.1 लाख मिलियन टन, 2020 में लगभग 39.8 लाख मिलियन टन, 2021 में लगभग 45.3 लाख मिलियन टन कोयला आपूर्ति हुआ था। जबकि अप्रैल एवं जून 2022 में लगभग 63 एवं 67 लाख मिलियन टन कोयले की आपूर्ति सुनिष्चित की गयी। विद्युत उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुये हैं। इस वर्ष की प्रथम तिमाही में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की इकाईयों द्वारा गत वर्ष के सापेक्ष विद्युत उत्पादन एवं पी0एल0एफ0 में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गयी। पिछले वर्ष माह अप्रैल से जून के बीच 7936 मि0यु0 का उत्पादन हुआ था जबकि 2022 के इन्ही महीनों में 10794 मि0यु0 विद्युत उत्पादन हुआ जो 36 प्रतिशत अधिक है।

उपभोक्ता सेवा में गुणात्मक सुधार करते हुए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाया। इसी प्रकार वितरण क्षेत्र में भी दो उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जीकृत किया। 33/11 के0वी0 जी0आई0एस0 (गैस इन्सूलेटेड उपकेन्द्र) उपकेन्द्र नगवां जनपद वाराणसी उपकेन्द्र की क्षमता 2X10 एम0वी0ए0 है तथा इसके ऊर्जीकरण से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नरीया तथा 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र डफी का भार कम किया गया। परिणाम स्वरूप उक्त तीनों उपकेन्द्रों से जुड़े लगभग 35000 उपभोक्ताओं को बेहतर एवं गुणवत्ता परक विद्युत आपूर्ति का अवसर प्राप्त हुआ। इस पर 20.65 करोड़ रूपये व्यय किये गये। 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र कैल्हा, चित्रकूट उपकेन्द्र का ऊर्जीकरण किया गया इससे क्षेत्र खम्भा खुर्द मडईयन, कैल्हा एवं षहरी क्षेत्रों के लगभग 7000 उपभोक्ताओं को बेहतर एवं गुणवत्ता परक विद्युत आपूर्ति का अवसर प्राप्त हुआ। इस पर 3. 49 करोड़ रूपये व्यय किये गये। अनमीटर्ड घरों में मीटर लगाने की कार्ययोजना बनाकर सर्वाधिक घरों में मीटर लगाने में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की गई। जिसके तहत 100 दिन के भीतर 3.68 लाख अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के यहॉ मीटर लगाने का लक्ष्य बनाया गया था। लक्ष्य के सापेक्ष जून 2022 तक 5.75 लाख उपभोक्ताओं के यहॉ मीटर लगाया जा चुका है। परिणाम स्वरूप अनमीटर्ड संयोजनों की संख्या जोकि 1 अप्रैल 2022 में 7.36 लाख थी से घटकर 1 जुलाई 2022 को 1.61 लाख तक आ गयी।

विद्युत आपूर्ति बेहतर करने हेतु पारेशण क्षेत्र में सात उपकेंद्रो का निर्माण कार्य पूर्णकर ऊर्जीकृत किया गया जिसके अन्तर्गत 400 के0वी0 रसड़ा उपकेन्द्र (बलिया) का रू0 426.06 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया साथ ही 400 के0वी0 भौखरी उपकेन्द्र (बस्ती), लागत रू0 829.59 करोड़, 220 के0वी0 उपकेन्द्र अयोध्या, लागत मूल्य 151.21 करोड़, 220 के0वी0 उपकेन्द्र बबीना (झांसी) लागत रू0 73.73 करोड़, 220 के0वी0 उपकेन्द्र मलवां (फतेहपुर) लागत रू0 100.17 करोड़, 132 के0वी0 उपकेन्द्र बिलोचपुरा (बागपत) लागत रू0 69.17 करोड़, 132 के0वी0 उपकेन्द्र छानवे (मीर्जापुर) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य लागत रू0 22.27 करोड़ से पूर्ण किया गया। रिवैम्पड योजना (आर0डी0एस0एस0) के अंतर्गत विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु रू0 54300.28 करोड़ का कार्य अनुमोदित किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत लाइन हानियों को कम करने, विद्युत वितरण तंत्र के आधुनिकीकरण तथा उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर लगाये जाना लक्षित है। एशियन डेवेलपमेन्ट बैंक (ए0डी0बी0) से प्राप्त ऋण के माध्यम से 24930 मजरों में 26000 किलोमीटर ए0बी0 केबलिंग का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है। पारेषण क्षेत्र में 2162 करोड़ की कुल लागत के एक 400 के0वी0, चार 220 के0वी0 तथा तीन 132 के0वी0 उपकेन्द्र एवं विभिन्न पारेषण तन्त्र की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है।

श्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर विद्युत उपलब्धता बढ़ाने हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किया जा रहा है। सरकारी एवं अर्धसरकारी भवनो में अब तक 1080 कि0वा0 क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ़ टॉप प्लान्ट स्थापित किये गये हैं। सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 5000 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्र स्थापित किये गये हैं। जनपद जालौन के अन्तर्गत 32 मे0वा0 एवं 65 मे0वा0 कुल 97 मे0वा0 क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जनपद हापुड़ में 5 टन कम्प्रेस्ड बायो गैस प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट का ट्रायल रन आरम्भ किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में निजी अवासो में ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप प्लान्ट स्थापना हेतु लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन आरम्भ किया जा चुका है। अब तक 972 लाभार्थियों के सापेक्ष 3024 कि0वा0 सोलर प्लान्ट क्षमता का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है।

नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास विभाग द्वारा 100 दिन में किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी के विजन स्वच्छ भारत के तहत नगरीय निकायों को साफ–स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए सर्वप्रथम अधिकारियों,

कर्मचारियों व जन भागीदारी के सहयोग से सभी नगरीय निकायों में प्रातः 05 बजे से 08 बजे के बीच सफाई व्यवस्था प्रारम्भ की गई। इसमें सभी सफाई कर्मियों के साथ जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने भी अपना अहम योगदान दिया और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सफाई कार्य में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था की मॉनीटरिंग एवं जन शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रदेश स्तरीय डेडीकेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना निकाय निदेशालय में की गई और यह व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग की भांति ही नगरीय निकायों में भी समस्याओं के निस्तारण हेतु 'सम्भव' पोर्टल की वैसी ही व्यवस्था की गई है, इसमें शिकायतकर्ता को सीधे मंत्री से भी संवाद का मौका मिलता है।

प्रदेश के 17 शहरों में यातायात व्यवस्था एवं नागरिक सुविधाओं की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई तथा 17 स्मार्ट सिटीज के कार्यों की निगरानी के लिए सेन्ट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग सेन्टर की स्थापना की गई और डेडीकेटड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से भी जोड़ा गया है। इसी प्रकार नागरिकों द्वारा सीधे शिकायत दर्ज करने के लिए भारत सरकार से 1533 टोल फ्री नं0 की व्यवस्था कर इसे राज्य स्तर पर संचालित किया गया, इससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में बहुत सी योजनाएं एवं परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसकी मॉनिटरिंग हेतु पी0एम0यू0 की स्थापना की गई। इसी प्रकार नवसृजित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना संचालित की गई और ऐसी नगरीय निकायों के विकास के लिए 550 करोड़ रुपये बजट प्रदान किया गया। साथ ही हैण्ड होल्डिंग की भी व्यवस्था शुरू की गई, इसके तहत 17 स्मार्ट सिटीज के 102 नगरीय निकायों के कार्यों में सहयोग मिलेगा। सरकार ने नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए नगरों के वातावरण को अच्छे से श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है, जिसके तहत अमृत उद्यान एवं अमृत सरोवर बनाये जायेंगे, इससे शहरों की गंदगी को हटाने में भी सहयोग मिलेगा। शहर की सफाई व्यवस्था, नालों/नालियों की सफाई की निगरानी के लिए ड्रोन से मॉनिटरिंग करने की पहली बार पहल की गई।

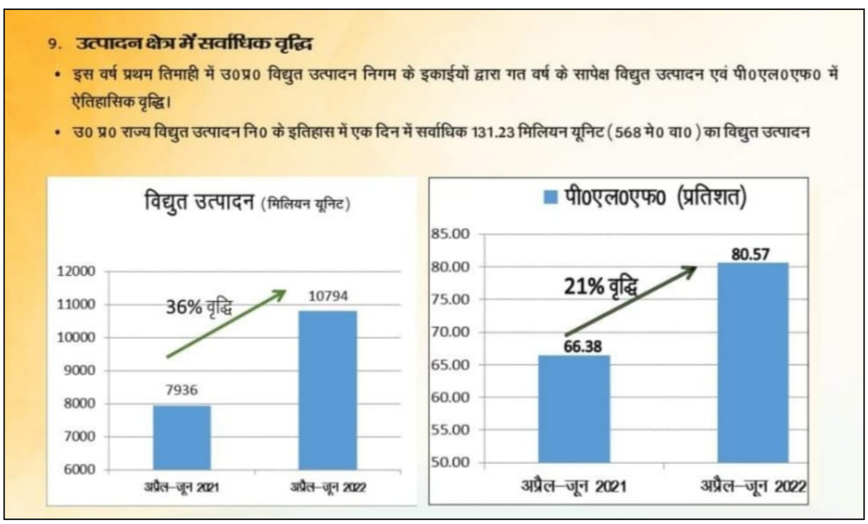

सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से प्रकृति और मानव जीवन को बचाने के लिए इसके प्रतिबंध हेतु जनजागरूकता के लिए 29 जून, 2022 को रेस अभियान चालू किया और पांच दिन के भीतर ही जन सहयोग के माध्यम से 05 हजार कुन्तल से अधिक की प्लास्टिक एकत्रित कर इसका निस्तारण किया गया। उन्होंने मीडिया से भी इसमें सहयोग देने की अपील की है और प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी के संदेश को अधिक से अधिक लोगों के बीच ले जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विभाग के 100 दिन के लक्ष्य को पूरा करते हुए पेयजल की 19 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। विभिन्न नगरीय निकायों में 280 सीट से अधिक पिंक शौचालय का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसी प्रकार डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रह का कार्य भी पूरी सतर्कता के साथ किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 50 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा अब तक 75 परिययोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार सेन्ट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग सेन्टर की स्थापना से 17 शहरों से लाइव फीड प्राप्त की जा रही है।

पी0एम0 स्वनिधि योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष 116950 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 87696 स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित किया गया। शहरों के प्रदूषण को कम करने तथा यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए 446 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। सिटी बस सेवा हेतु 'चलो ऐप' की भी शुरूआत की गई। निकायों में 65 अंत्येष्टि स्थलों को कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 17 निराश्रित गोवंश के लिए 17 गौशालाओं का कार्य पूर्ण कर क्रियाशील किया गया है। शहरों में अमृत पार्क के तहत 35 पार्कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शहरों में ऑनलाइन प्रापर्टी म्यूटेशन की व्यवस्था भी संचालित की गई। उन्होंने कहा कि शहरी व्यवस्था में सुधार के लिए अधिक से अधिक मशीनों के प्रयोग पर बल दिया गया है और हजरतगंज जैसे अन्य व्यस्तम इलाकों में दोपहर एवं सायं में भी सफाई कराने की व्यवस्था की गई है।

प्रेसवार्ता में ऊर्जा राज्यमंत्री श्री डा0 सोमेन्द्र तोमर, नगर विकास राज्यमंत्री श्री राकेश राठौर 'गुरू', अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री अवनीश कुमार अवस्थी, चेयरमैन पावर कारपोरेशन श्री एम0देवराज, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव नगर विकास श्री रंजन कुमार, एम0डी0 वितरण श्री पी0गुरू प्रसाद, एम0डी0 जल निगम श्री अनिल कुमार, एम0डी0 पावर कारपोरेशन श्री पंकज कुमार, निदेशक सूचना श्री शिशिर, निदेशक लोकल बॉडी सुश्री नेहा शर्मा एवं निदेशक सूडा सुश्री यशू रूस्तगी आदि उपस्थित थे।

हमारी प्रेरणा राष्ट्रध्वज तिरंगा

किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसका सर्वाधिक सभादृत प्रतीक होता है। वर्षों के सतत् संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली हम स्वतंत्र हुए। इस महासंग्राम में जो गीत, उद्‌घोष ध्वज हमारी प्रेरणा रहे, वह संविधान में जाकर हमारे प्रतीक बने जिसमें से उदित तिरंगा हमारा आराध्य है।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, तीन रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई, 1947 को आयोजित भारतीय संविधान–सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें तीन समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है ओर नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें चक्र में 24 तीलियां होते हैं। यह इस बात प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है। भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है।

गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें दो रंग थे लाल रंग हिन्दुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मो के लिए सफेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉ॰ बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने लगवाया। इस नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की।

तिरंगे की कहानी

यह ध्वज भारत की स्वतंत्रता के संग्राम काल में निर्मित किया गया था। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और उसके साथ ही वह योजना भी बीच में ही अटक गई थी। वर्तमान रूप में पहुँचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनैतिक विकास का परिचायक भी है। कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं :–

- प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त, 1906 को पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क) कलकत्ता में इसे कांग्रेस के

अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में आठ कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चाँद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदेमातरम् लिखा गया था।

- द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ. निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1905 में हुआ था। यह भी पहले ध्वज के समान था। सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु सात तारे सप्तऋषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था।

- 1917 में भारतीय राजनैतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉ0 एनी बीसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियाँ एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर सात सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बायीं ओर (खंभे की ओर) यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था।

- कांग्रेस के अधिवेशन विजयवाड़ा में किया गया यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वैंकैया ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह दो रंगों का बना था। लाल और हरा रंग जो दो प्रमुख समुदायों अर्थात हिन्दू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए।

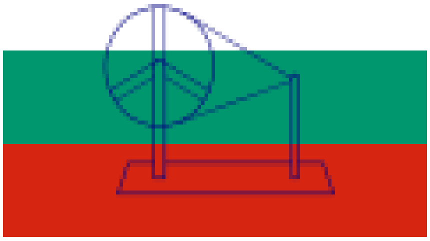

- वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र–ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई साम्प्रदायिक महत्त्व नहीं था।

- 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। इसके सम्मान, आदर में अमृत महोत्सव वर्ष पर 15 अगस्त को अपने घर पर इसे फहराये।

अगला दशक भारत का दशक है

आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के पिछले आठ वर्षों में भारत 'सबका साथ और सबका विकास' के प्रमुख सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका है और भारत की विकास गाथा प्रधानमंत्री मोदीजी की आत्मनिर्भरता और गरीब कल्याण के संकल्प एवं सर्वस्पर्शी व सर्व-समावेशी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। इसी लय से राष्ट्र की यह विकास गाथा और गतिमान होती रहेगी। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के सत्ता संभालने के बाद वास्तव में भारत का चहुंमुखी विकास हुआ है। आठ वर्षों में देश की इतनी प्रगति प्रधानमंत्री मोदीजी की सोच का परिणाम है। हमें 2014 के चुनाव में प्रचंड जीत के कुछ ही घंटों बाद मोदीजी द्वारा दिया गया वह विजय-भाषण आज भी स्मरण है। उसमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि भारत का समावेशी विकास करना है। उन्हें पता था कि इसके लिए उन्हें डिलीवरी तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। कांग्रेस के शासन में योजनाएं और नीतियां कागजों में सिमट कर रह जाती थीं। डिलीवरी तंत्र में छेद ही छेद थे। हर जगह लूटखसोट थी। किंतु मोदीजी की सरकार आई और योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया। मोदीजी के डिलिवरी तंत्र में सुनिश्चित किया गया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। इस सफलता के पीछे प्रधानमंत्री मोदीजी का 'सबका साथ-सबका विकास' मंत्र था। कांग्रेस शासन के समय सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ चेहरा और पहचान देखकर दिया जाता था, कांग्रेस के शासन में योजनाएं वोट बैंक की राजनीति करते हुए कुछ विशेष समूहों या जातियों के लिए ही बनाई जाती थीं। प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने यह पक्षपाती व्यवस्था बदली और सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाएं देश के प्रत्येक नागरिक के लिए हों और इनका लाभ निष्पक्षता से सभी वर्गों, समुदायों और व्यक्तियों को मिले।

> **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने न केवल कोवैक्सिन नामक अपनी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लगभग तुरंत ही विकसित कर ली, अपितु विदेशों में विकसित कोविशील्ड वैक्सीन का स्वदेश में साझेदारी के आधार पर उत्पादन भी किया**

प्रधानमंत्री मोदीजी की सोच से जो एक और नया प्रतिमान आया, वह यह था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए।

प्रधानमंत्री मोदीजी ने देश में यह विश्वास भरा कि हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास श्रमशक्ति है, हमारे पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं। हम सर्वश्रेष्ठ उत्पाद बनाएंगे, 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी करेंगे, और अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में ले जाने के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदीजी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना 'वसुधैव कुटुंबकम' पर आधारित है जब भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है तो यह स्व-केंद्रित प्रणाली का पक्ष नहीं लेता है। भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प में समस्त विश्व के सुख, सहयोग और शांति का भाव निहित है।

प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा भारत की आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए पांच क्षेत्र चुने गए हैं:

- **अर्थव्यवस्था:** ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि क्रमिक परिवर्तन के बजाय एक साथ बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला हो।
- **मूलभूत अवसंरचना:** ऐसी मूलभूत अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान और विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला हो।
- **तंत्र:** ऐसा तंत्र हो जो आधुनिक प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने वाला हो और समाज में डिजिटल तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने वाला हो।
- **जनांकिकी:** अपनी बहुमुखी प्रतिभावान और युवा जनांकिकी का सर्वोत्तम उपयोग हो।
- **मांग:** हमारे पास बड़े स्तर पर घरेलू बाजार और मांग वाले क्षेत्र हैं, जिनका पूरी क्षमता से दोहन हो।

कोविड राहत और पुनरुत्थान

आदरणीय प्रधानमंत्रीजी के दूसरी बार पदभार संभालने के तुरंत बाद विश्व के साथ-साथ भारत को भी एक वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। यद्यपि, भारत न केवल अपने लोगों की रक्षा करने और मानवता की सहायता के लिए लगभग 100 देशों तक सहायता का हाथ बढ़ाने में सफल रहा, अपितु प्रत्येक स्तर पर और शक्तिशाली होकर उभरा। कुशल प्रशासन, नवोन्मेषी सोच, अच्छी तरह से जांची-परखी नीतियां, जन-कल्याण की नीतियों का त्वरित क्रियान्वयन और 1.35 अरब लोगों की सेवा करने की अटूट प्रतिबद्धता ने इस सफलता के मार्ग को प्रशस्त किया।

रिकार्ड समय में भारत की स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन और वितरण सफलता की उल्लेखनीय गाथा है। भारत ने डेढ़ वर्ष में अपने नागरिकों को 191 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक दी है। ध्यान रहे, यह वही भारत है जिसे विदेशों में खोज हो जाने के पश्चात भी पोलियो वैक्सीन के लिए 30 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने न केवल कोवैक्सिन नामक अपनी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लगभग तुरंत ही विकसित कर ली, अपितु विदेशों में विकसित कोविशील्ड वैक्सीन का स्वदेश में साझेदारी के आधार पर उत्पादन भी किया। सरकार के सूक्त वाक्य 'वसुधैव कुटुंबकम' पर आगे बढ़ते भारत ने लगभग 100 देशों को इन टीकों का निर्यात किया। महामारी के समय मृत्यु दर और रुग्णता दोनों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य का मूलभूत ढांचा महत्वपूर्ण था। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश भर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की

मूलभूत अवसंरचना को तेजी से हजारों गुना बढ़ाया है। उदाहरण के लिए देश में गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू) में पेशेंट बेड्स की संख्या मार्च 2020 में 2,168 थी, जिसे जनवरी, 2022 तक बढ़ाकर 1.39 लाख कर दिया गया। इसी अवधि में देशभर में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन (पीएसए) प्लांट्स (ऑक्सीजन प्लांट्स) और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट की निर्माण क्षमता भी इसी परिमाण में बढ़ाया गया। यह देश के स्वास्थ्य ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन और सशक्त रूपांतरण को दर्शाता है।

आर्थिक पुनरुद्धार- पहल, वृहद-दृष्टिकोण और लक्षण

कोविड-19 ने न केवल भारत, अपितु विश्व के लगभग सभी देशों की आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया। संक्रमण के भय ने श्रम-बल की भागीदारी के साथ-साथ श्रमिकों को काम पर रखने के लिए नियोक्ताओं की इच्छा को भी प्रभावित किया। अनेक प्रकरणों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकारों द्वारा लॉकडाउन लगाए गए, जिसने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। एक दूसरे से जुड़े विश्व में, जहां कहीं भी उत्पादन में व्यवधान आया, वहां इससे आपूर्ति-शृंखला टूटी और इसने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। ऐसे वातावरण में भारत में स्थिर कीमतों पर 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में -6.6 प्रतिशत हो गई थी, किंतु भारत महामारी के कुशल प्रबंधन के साथ ही 2021-22 में अनुमानित 8.7 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने में सफल रहा। आवासन क्षेत्र में बाजार के उभरने के प्रत्यक्ष संकेत दिख रहे हैं।

महामारी और यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद से ही हमारी सरकार ने असाधारण उपाय किए हैं। हमने अपने महान देश के आमजन और महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं आरंभ की हैं और कदम उठाए हैं। हमने छोटे व्यापार को ऊपर उठाने के लिए अनेक उपाय किए हैं और इसके लिए बड़े परिमाण में धन की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मोदीजी ने अनेक दीर्घावधि योजनाएं आरंभ कर इस देश के भविष्य को सुरक्षित करने का कदम उठाया है। हम अपने प्रधानमंत्रीजी को नमन करते हैं कि उन्होंने ऋण/जीटीपी और वित्तीय समझदारी के पथ को अपनी सरकार की घोषित परिधि में रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि हम अपने साधनों से अधिक व्यय न करें और न ही क्षमता से अधिक बोझ डालें।

भारत के रिकॉर्ड निर्यात प्रदर्शन की प्रत्येक स्थान पर भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है और बहुतों ने भारत के उत्प्लावक निर्यात प्रदर्शन का लक्ष्य मन में पाल रखा है। इसके स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। 2021-22 में सेवा क्षेत्र का निर्यात 25,000 करोड़ डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 21.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा। 2021-22 में भारत का कुल निर्यात (व्यापार व सेवा मिलाकर) 34.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 66,965 करोड़ डॉलर पहुंच गया। लौह और इस्पात के निर्यात का मूल्य 2013-2014 के 7.64 अरब डॉलर की तुलना में 2021-2022 में बढ़कर 19.25 अरब डॉलर हो गया है। इसी प्रकार, 2013-14 के बाद पिछले 8 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ट्रैक्टरों के निर्यात में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2017-18 के 1300 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन के निर्यात की तुलना में 2021-22 में लगभग 43,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात किए गए।

भारत सरकार ने वृहद अर्थशास्त्र के सुदृढ़ सिद्धांतों के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा है और भारत की यह आर्थिक सुदृढ़ता निवेशकों की भावनाओं में पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है। पंजीकृत निवेशकों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। अपने घरेलू समकक्षों के जैसे, विदेशी निवेशकों ने भी बड़े परिमाण में निवेश करके भारत में विश्वास व्यक्त किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2021-22 में 83.50 अरब डॉलर के उच्च स्तर को छू गया। 2014 से पहले 2013-14 में एफडीआई मात्र 36.50 अरब डॉलर था।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए ऋणों में 2021-22 में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साख वृद्धि को महामारी के पहले वाली स्थिति में लाने में सफलता मिली और यह उत्साहजनक संकेत है, जिससे समग्र आर्थिक विकास में तेजी आने की संभावना है। भविष्य के अवसरों और 'न्यू इंडिया' के निर्माण को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं; जैसे कि बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन करने वाले विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं। ये योजनाएं व्यापक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर, कपड़ा, एलईडी लाइट और ऑटोमोटिव उत्पाद क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने की बड़ी क्षमता के साथ 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 करोड़ रुपये की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने इस तथ्य को समझा कि माइक्रो चिपों की आपूर्ति के लिए हम बाहर की कंपनियों पर निर्भर हैं। हमें यह उल्लेख करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदीजी ने माइक्रो चिप पर विदेशों की निर्भरता समाप्त करने और आईटी क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में माइक्रो चिप उत्पादन पर बल दिया और इस दिशा में प्रभावी पहल की है।

मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत मोदी सरकार ने 3.19 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 1.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बनने से बचाया गया। सरकार के इस प्रयास से देश में 13.5 लाख एमएसएमई को बचाया गया, जो कि भारत के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस योजना ने न केवल लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की, अपितु 1.5 करोड़ रोजगार सृजनकर्ताओं को भी बचाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 6 करोड़ लोगों की आजीविका

बची। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने जून 2022 की वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन में कहा है कि मार्च, 2022 में सकल एनपीए अनुपात छह वर्ष के सबसे निचले स्तर 5.9 प्रतिशत पर आ गया है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भविष्य की ओर देखती एक महात्वाकांक्षी परियोजना है। 100 लाख करोड़ रुपए की मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की यह योजना व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही व परिवहन के लिए एक साधन से दूसरे साधन में एकीकृत और निर्बाध संबद्धता देने से साथ एक-दूसरे को जोड़ेगी। इससे अंतिम छोर तक मूलभूत ढांचे की संबद्धता की सुविधा मिलेगी। साथ ही, यह लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा। इस परियोजना के विस्तार से मूलभूत ढांचा क्षेत्र में हजारों रोजगार व नौकरियां उत्पन्न होंगी।

प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा कर सरकार में 10 लाख नौकरियां सृजित करने का वचन दिया है। केंद्र सरकार द्वारा 'मिशन मोड' में भर्ती करने की घोषणा से रक्षा, रेलवे और राजस्व जैसे क्षेत्रों में नौकरी चाहने वालों को सहायता मिलेगी। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित अग्निपथ योजना न केवल सशस्त्र बलों में सम्मिलित होने और राष्ट्र की सेवा करने के उनके सपने को पूरा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी, अपितु उन्हें सशक्तीकरण, अनुशासन और कौशल भी प्रदान करेगी।

सरकार ने पिछले आठ वर्षों में उचित मूल्य स्थिरता बनाए रखी है। हाल ही में, जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव देखा गया, वहीं थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में मापी गई मुद्रास्फीति, भू-रणनीतिक अनिश्चितताओं के कारण, आंशिक रूप से अस्थिर रही है। मोदी सरकार ने उचित मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए ठोस उपाय किए हैं।

'एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर' के विचार से प्रस्तुत किये गए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की प्रशंसा भारत के इतिहास में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में हुई है। देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समान कर लगाने के लिए जीएसटी ने करों की बहुलता और नकारात्मकता को समाप्त किया है। यह अर्थव्यवस्था के विकास का एक अच्छा उपाय है और संतोष की बात यह है कि जीएसटी संग्रह अप्रैल, 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। लेखा परीक्षण और विश्लेषण के सराहनीय प्रयासों से करवंचना (कर चोरी) करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिससे कर अनुपालन संस्कृति बन रही है। यह महत्वपूर्ण होगा कि इसको आगे बढ़ाते हुए कर अनुपालन संस्कृति में सुधार और गति बनाए रखी जाए।

गरीबी उन्मूलन

कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में आरंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 25 महीने तक निःशुल्क अनाज (राशन) दिया गया। यह योजना अप्रैल 2020 से चलाई जा रही है और यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने अब तक 2.60 लाख करोड़ रुपए व्यय किए हैं और अगले छह मास में सितंबर 2022 तक अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। पीएमजीकेएवाई ने घोर निर्धनता को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने भी योजना की इस भूमिका को स्वीकार किया है।

कृषक समुदाय का उत्थान और जीवन स्तर में सुधार हमारे प्रधानमंत्री मोदीजी की सर्वाधिक प्राथमिकता में है। किसान सम्मान निधि योजना गेम चेंजर है। इसके अंतर्गत 11.78 करोड़ किसानों को 10 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में 1.82 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 2009-2014 (मनमोहन सरकार) के पांच वर्ष में देश के कृषि बजट में नाममात्र की 8.5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। जबकि श्री नरेन्द्र मोदीजी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 2014 से 2019 के बीच कृषि बजट में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा मोदी सरकार की किसान हितैषी मंशा, नीति और नेतृत्व का साक्ष्य है।

कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में आरंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कीसबसे बडी योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 25 महीने तक निःशुल्क अनाज दिया गया

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आर्थिक लाभ

दशकों से सरकारें जटिल वितरणात्मक न्याय एवं अंतर-पीढ़ीगत सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए आधे-अधूरे मन से प्रयास कर रही थीं। भाजपा सरकार ने नीति-निर्माण को समाज के सबसे निर्धन वर्गों को समावेशित करने पर केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदीजी देश के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वच्छता जैसे विषयों पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है। यह विषय ग्रामीण जनसंख्या की भलाई के लिए केंद्रित है। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, पीएम आवास योजना, सौभाग्य और जल जीवन मिशन जैसी राष्ट्रव्यापी योजनाओं की डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन ने यह सुनिश्चित किया है कि लाखों निर्धन लोगों का जीवन मौलिक रूप से परिवर्तित हो। उनके जीवन स्तर में कई गुना सुधार हुआ है।

'जल जीवन मिशन' का उद्देश्य सभी घरों में नल से जल पहुंचाना है। यह मिशन 'जीवन की गुणवत्ता' को उत्तम बनाने के लिए पूरे वेग से कार्य कर रहा है। यह मिशन उन महिलाओं के लिए 'जीवन की सुगमता' में वृद्धि कर रहा है जो जल एकत्र करने के लिए हर दिन

लंबे, थकाऊ घंटे बिताती हैं। देश के 83 जनपद पहले ही 'हर घर जल' जनपद बन चुके हैं। पिछले दो वर्षों में नल के पानी के कनेक्शन वाले परिवारों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे परिवारों की संख्या बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। इस प्रकार देश में नल के पानी के कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या लगभग 17 प्रतिशत से बढ़कर 47.19 प्रतिशत हो गई है। जब यह मिशन 2024 तक पूरा होगा, देश के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल, नल कनेक्शन का पानी होगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रियायती एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं। इस प्रकार महिलाओं को एक सुविधा के स्वामित्व के माध्यम से अधिक सम्मान प्रदान किया गया। उज्ज्वला योजना महिलाओं को धुआं मुक्त वातावरण प्रदान करती है और ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने के कठिन परिश्रम को कम करती है, जिससे उनका समय और स्वास्थ्य बचता है। 2022-23 के बजट में एलपीजी के लिए कम सब्सिडी आवंटन करने की आवश्यकता लगी, जिससे यह उत्साहजनक संकेत मिलता है कि भारत में एलपीजी पैठ में लगभग 99 प्रतिशत संतुष्टि है। ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली घोषणा की दिशा में ये कदम दूरगामी परिणाम देने वाला है।

आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सामाजिक कल्याण योजनाएं परिवारों को स्वास्थ्य गरीबी के जाल में गिरने से बचा रही हैं। इन दोनों योजनाओं की उपलब्धि को कम नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये उपचार के बजाय रोकथाम करती हैं। आयुष्मान भारत सबसे गरीब 50 करोड़ भारतीयों को प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुरक्षा की गारंटी देता है।

वित्तीय और डिजिटल समावेशिता

प्रधानमंत्री जनधन योजना और डिजिटल इंडिया के शुभारंभ के साथ वित्तीय और डिजिटल समावेशिता को शीघ्रता के साथ स्थापित किया गया था। सभी जनधन बैंक खातों में 55 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं। जनधन योजना से 24.42 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। नाबार्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बैंक से जुड़े 1.1 करोड़ स्वयं सहायता समूहों में से 97 लाख विशेष महिला स्वयं सहायता समूह हैं। अपने इन महिलाओं का स्वयं के बैंक खातों पर नियंत्रण के साथ बैंकिंग उपकरणों की श्रृंखला तक पहुंच है।

जेएएम (जैम) ट्रिनिटी, अर्थात जनधन खाता, आधार और मोबाइल एक साथ, महिलाओं को बड़ी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर रहे हैं। कोविड-19 के कठिन समय में इन प्रभावशाली और राष्ट्रीय स्तर पर निष्पादित नीतियों का बड़ा लाभ देखा गया। जनधन खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से महिलाओं को (तीन महीने तक 500 रुपए प्रतिमाह) 30,944 करोड़ रुपये वितरित किए गए। जेएएम ट्रिनिटी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 400 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलियों और सहवर्ती शाखा के सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित हो। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14 करोड़ से अधिक निःशुल्क एलपीजी रिफिल प्रदान किए गए। रीयल-टाइम लेन-देन (ट्रांजैक्शन) की दिशा में भारत ने डिजिटल इंडिया की मौन क्रांति रच डाली है। 2021 में भारत में 4860 करोड़ रीयल-टाइम लेन-देन हुए, जो कि चीन की तुलना में तीन गुना अधिक है और अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस व जर्मनी के संयुक्त रीयल-टाइम लेन-देन से सात गुना अधिक है।

उद्यमिता को प्रोत्साहन

पीएम-स्वनिधि भारत में धरातल पर उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने की अनूठी योजना है। योजना के अंतर्गत 31.90 लाख रेहड़ी-पटरी वालों का ऋण स्वीकृत किया गया। स्टैंड-अप इंडिया योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं को 30,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 35 करोड़ उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

भारतीय स्टार्ट अप पारिस्थिकी तंत्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और छिपी हुई भारतीय उद्यमशील प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने से जी उठा है। इसका साक्ष्य यह है कि आज बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां अरबों डॉलर की लुभावनी यूनीकार्न श्रेणी में प्रवेश कर रही हैं।

अगला दशक भारत का दशक है और यह लक्ष्य आत्मनिर्भरता के बिना पूरा नहीं होगा। आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए देश के गरीबों के उत्थान के प्रति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की प्रतिबद्धता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में कहर बरपाया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंद किया। जहां सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विकास पथ पर वापस आने के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत, महामारी के अपने कुशल प्रबंधन, सुविचारित नीतिगत प्रतिक्रिया, प्रो-एक्टिव् प्रो-रेस्पोंसिव और प्रो-पुअर नीति और इसके त्वरित क्रियान्वयन के कारण, इससे उबर कर प्रगति व विकास की नई कहानी लिखने के लिए तैयार खड़ा है।

भारत महामारी के अपने कुशल प्रबंधन और के कारण ठीक होने के पथ पर है। आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर 8.2 प्रतिशत होगी। उभरती अर्थव्यवस्थाओं सहित विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में यह सबसे आशाजनक विकास अनुमान है। केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अपने सभी प्रयास और ऊर्जा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में सही स्थान पुनः दिलाने के लिए समर्पित करना चाहिए। ■

साक्षात्कार

गुजरात दंगाः सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की जाकिया जाफरी की याचिका, प्रधानमंत्री मोदी को क्लीनचिट

जिन लोगों ने आरोप लगाए, वे मोदीजी से माफी मांगें : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से एएनआई(ANI) के 25 जून, 2022 को साक्षात्कार लिया जिसके अंश

- गुजरात दंगों के मामले में एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी और तथाकथित समाज सेवा के नाम का चोला ओढ़े तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना सच्चाई की जीत है, संविधान में हमारी आस्था की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सिद्ध किया है कि ये सभी आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटिड थे।
- हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18-19 साल की लड़ाई में एक शब्द बोले बगैर सभी दुःखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर हर वेदना को सहन कर लड़ते रहे। जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर विजयी होकर आता है तो उसकी चमक सोने से भी ज्यादा होती है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकतंत्र में संविधान के सम्मान का एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दंगे का जो दाग जबरन लगाया गया था, वह भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से धुला है।
- एसआईटी के गठन का ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग की थी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार से इस पर कंसेंट के लिए पूछा था। हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं है तो एसआईटी पर हमें क्या आपत्ति है। हमारी सरकार के कंसेंट पर एसआईटी का गठन किया गया था।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने अपने साक्षात्कार में सही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर झूठा आरोप लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अब माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों को कोरे झूठे के तौर पर उजागर किया जा चुका है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसके फैसले के लिए धन्यवाद।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

- एसआईटी के अफसरों का चयन भी हमने नहीं किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। इसमें शामिल अफसर भी भाजपाशासित राज्यों से नहीं लिए गए थे, केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए थे। उस समय तक केंद्र में यूपीए की सरकार आ चुकी थी। पूरी जांच कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान हुई।

- एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से घंटों पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने भी धरना-प्रदर्शन नहीं किया। हम मानते थे कि हमें न्याय प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। हमारा मानना है कि कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। जिन-जिन लोगों ने भी मोदीजी पर झूठे आरोप लगाए थे, यदि उनकी अंतरात्मा जागृत है तो आज उन्हें श्री नरेन्द्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से क्षमा मांगना चाहिए।
- भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ ख़ास एजेंडा लेकर राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन झूठे आरोपों को इतना प्रचारित किया। इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि धीरे-धीरे झूठ को ही सब सच मानने लगे।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह साफ़ है कि एक पुलिस अफसर, एक एनजीओ और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने मिलकर सनसनी फैलाने के लिए झूठी बातों को फैलाया और झूठे सबूत गढ़े। जब ये एसआईटी को जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि झूठा जवाब है जिसे एसआईटी ने भी बाद में न्यायालय के सामने रखा कि ये झूठे जवाब थे।
- देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट कर दिया कि गुजरात सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने बार-बार शांति की अपील की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए, वो सुनियोजित नहीं थे, स्वतः स्फूर्त थे। निहित स्वार्थ के तहत एक मैगजीन द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को भी न्यायालय ने खारिज कर दिया, क्योंकि जब इस स्टिंग का पूरा फुटेज सामने आया, तब मालूम पड़ा कि स्टिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
- जिस प्रकार से मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उसकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से धज्जियां उड़ा दी है। मैं मानता हूं कि यह जजमेंट भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का विषय है। ■

केन्द्र सरकार की उपलब्धियां

कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने 29 जून को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने व विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी।

इस परियोजना में कुल 2,516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 1528 करोड़ रुपये की होगी, के साथ पांच वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है।

कुल 2,516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 63,000 कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इस कदम से लगभग 13 करोड़ किसानों, जिनमें से अधिकांश छोटे व सीमांत किसान हैं, को लाभ होगा।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) की त्रि–स्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाती हैं, जहां लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए केसीसी ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) है और पैक्स के माध्यम से इन केसीसी ऋणों में से 95 प्रतिशत (2.95 करोड़ किसान) छोटे व सीमांत किसानों को दिए गए हैं। अन्य दो स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित कर दिया गया है और उन्हें साझा बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) के तहत ला दिया गया है।

हालांकि, अधिकांश पैक्स को अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है और वे अभी भी हस्तचालित तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके संचालन में अक्षमता और भरोसे की कमी दिखाई देती है। कुछ राज्यों में पैक्स का कहीं–कहीं और आंशिक आधार पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर में कोई समानता नहीं है और वे डीसीसीबी एवं एसटीसीबी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में पूरे देश में सभी पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने और उनके रोजमर्रा के कार्य–व्यवहार के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा मंच पर लाने तथा एक सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) के तहत रखने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने तथा किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों (एसएमएफ) को दी जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने के अलावा पैक्स का कम्प्यूटरीकरण विभिन्न सेवाओं एवं उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बेहतर बनाने के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ–साथ गैर–बैंकिंग गतिविधियों के केन्द्र के रूप में पैक्स की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना हुई चालू

भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना अब पूरी तरह से चालू हो गई है। एनटीपीसी ने 1 जुलाई की आधी रात से रामागुंडम, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम तैरती सौर पीवी परियोजना में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की।

एनटीपीसी–रामगुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना पूरी तरह से संचालित। दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया।

रामागुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया। इससे पहले एनटीपीसी ने कायमकुलम (केरल) में 92 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा और सिम्हाद्री (आंध्र प्रदेश) में 25 मेगावाट तैरती सौर ऊर्जा के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की।

रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर परियोजना उन्नत तकनीक के साथ–साथ पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं से संपन्न है। मेसर्स भेल के माध्यम से ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण) अनुबंध के रूप में 423 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है।

केन्द्र सरकार की उपलब्धियां

जून, 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह साल-दर-साल 56% बढ़कर 1,44,616 करोड़ रुपये हुआ

जून, 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल, 2022 के संग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। जीएसटी लागू होने के बाद से पांचवी बार जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार हुआ और मार्च, 2022 से लगातार चौथा महीना है

जून, 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 144,616 करोड़ रुपये का रहा, जिसमें सीजीएसटी 25,306 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,406 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 75,887 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 40,102 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,018 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 1197 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। जून, 2022 में सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल, 2022 के 1,67,540 करोड़ रुपये के संग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।

केंद्र सरकार ने आईजीएसटी से 29,588 करोड़ रुपये का सीजीएसटी और 24,235 करोड़ रुपये का एसजीएसटी में निपटान किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने इस महीने में केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर 27,000 करोड़ आईजीएसटी का निपटान किया है। जून, 2022 में नियमित निपटान

के बाद केन्द्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 68,394 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 70,141 करोड़ रुपये रहा।

जून, 2022 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में संग्रह किए गए 92,800 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व से 56 प्रतिशत अधिक है। इस मास के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 55 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेन-देन से प्राप्त राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 56 प्रतिशत अधिक है।

यह पांचवीं बार है जब जीएसटी की स्थापना के बाद से मासिक जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया और मार्च, 2022 के बाद से चौथा महीना है। जून, 2022 में संग्रह न केवल दूसरा सबसे अधिक रहा, बल्कि कम मासिक संग्रह होने की प्रवृत्ति को भी तोड़ दिया है, जैसाकि अतीत में देखा गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपया रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 1.10 लाख करोड़ रुपये के औसत मासिक संग्रह के मुकाबले 37% की वृद्धि दर्शाता है। आर्थिक सुधार के साथ चोरी-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। इस महीने में सकल उपकर संग्रह जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अधिक है। ■

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 30 प्रतिशत से अधिक बढ़कर अब तक का सर्वाधिक 57,586.48 करोड़ रुपये रहा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 जून को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने बड़ी बाधाओं के बावजूद 2021-22 के दौरान 57,586.48 करोड़ रुपये (7.76 बिलियन डॉलर) मूल्य के 13,69,264 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निर्यात में रुपये के संदर्भ में 31.71 प्रतिशत, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 30.26 प्रतिशत तथा मात्रा की दृष्टि से 19.12 प्रतिशत का सुधार हुआ। 2020-21 में भारत ने 43,720.98 करोड़ रुपये मूल्य के (5,956.93 मिलियन डॉलर) 11,49,510 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य उत्पाद का निर्यात किया था।

गौरतलब है कि कोविड महामारी के कारण प्रमुख निर्यात बाजारों में उत्पन्न अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत 7.76 बिलियन डॉलर मूल्य के 13,69,264 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का निर्यात किया जो अब तक का सबसे अधिक सफल निर्यात प्रबंधन रहा।

विदेशी बाजारों में अमेरिका, भारतीय समुद्री खाद्य का मूल्य तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से प्रमुख आयातक बना रहा। अमेरिका ने 3371.66 मिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया और डॉलर मूल्य में इसकी हिस्सेदारी 37.56 प्रतिशत रही।

मात्रा की दृष्टि से चीन भारत से समुद्री खाद्य निर्यात का दूसरा सबसे बड़े स्थान के रूप में उभरा, चीन ने 1,175.05 अमेरिकी डॉलर मूल्य का 2,66,989 मीट्रिक टन आयात किया। भारतीय समुद्री खाद्य का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थान यूरोपीय यूनियन रहा। ■

23 जुलाई जयंती विशेष

अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों में चन्द्रशेखर आजाद का नाम सदा अग्रणी रहेगा। उनका जन्म 23 जुलाई, 1906 को ग्राम माबरा (झाबुआ, मध्य प्रदेश) में हुआ था। उनके पूर्वज गाँव बदरका (जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश) के निवासी थे; पर अकाल के कारण इनके पिता श्री सीताराम तिवारी माबरा में आकर बस गये थे।

बचपन से ही चन्द्रशेखर का मन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर सुलगता रहता था। किशोरावस्था में वे भागकर अपनी बुआ के पास बनारस आ गये और संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ने लगे। बनारस में ही वे पहली बार विदेशी सामान बेचने वाली एक दुकान के सामने धरना देते हुए पकड़े गये। थाने में हुई पूछताछ में उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतन्त्रता और घर का पता जेलखाना बताया। इस पर बौखलाकर थानेदार ने इन्हें 15 बेंतों की सजा दी। हर बेंत पर ये 'भारत माता की जय' बोलते थे। तब से ही इनका नाम 'आजाद' प्रचलित हो गया।

आगे चलकर आजाद ने सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से देश को आजाद कराने वाले युवकों का एक दल बना लिया। भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, मन्मथनाथ गुप्त, शचीन्द्रनाथ सान्याल, जयदेव आदि उनके सहयोगी थे।

आजाद तथा उनके सहयोगियों ने नौ अगस्त, 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेल को काकोरी स्टेशन के पास रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। यह अंग्रेज शासन को खुली चुनौती थी, अतः सरकार ने क्रान्तिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी।

पर आजाद को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वे वेष बदलकर क्रान्तिकारियों के संगठन में लगे रहे। ग्वालियर में रहकर इन्होंने गाड़ी चलाना और उसकी मरम्मत करना भी सीखा।

17 दिसम्बर, 1928 को इनकी प्रेरणा से ही भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने सांडर्स को यमलोक पहुँचा दिया। अब तो पुलिस बौखला गयी; पर क्रान्तिवीर अपने काम में लगे रहे।

कुछ समय बाद क्रान्तिकारियों ने लाहौर विधानभवन में बम फेंका। यद्यपि उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। बम फेंककर भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके वीरतापूर्ण वक्तव्यों से जनता में क्रान्तिकारियों के प्रति फैलाये जा रहे भ्रम दूर हुए। दूसरी ओर अनेक क्रान्तिकारी पकड़े भी गये। उनमें से कुछ पुलिस के अत्याचार न सह पाये और मुखबिरी कर बैठे। इससे क्रान्तिकारी आन्दोलन कमजोर पड़ गया।

वह 27 फरवरी, 1931 का दिन था। पुलिस को किसी मुखबिर से समाचार मिला कि आज प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद किसी से मिलने वाले हैं। पुलिस ने समय गँवाये बिना पार्क को घेर लिया। आजाद एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उनकी निगाह पुलिस पर पड़ी, वे पिस्तौल निकालकर पेड़ के पीछे छिप गये।

कुछ ही देर में दोनों ओर से गोली चलने लगी। इधर चन्द्रशेखर आजाद अकेले थे और उधर कई जवान। जब आजाद की पिस्तौल में एक गोली रह गयी, तो उन्होंने देश की मिट्टी अपने माथे से लगायी और उस अन्तिम गोली को अपनी कनपटी में मार लिया। उनका संकल्प था कि वे आजाद ही जन्मे हैं और मरते दम तक आजाद ही रहेंगे। उन्होंने इस प्रकार अपना संकल्प निभाया और जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आये।

श्री जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति पद हेतु नामांकन

नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
जुलाई द्वितीय अंक 2022 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

हमाओ बुन्देलखण्ड हमाईशान...

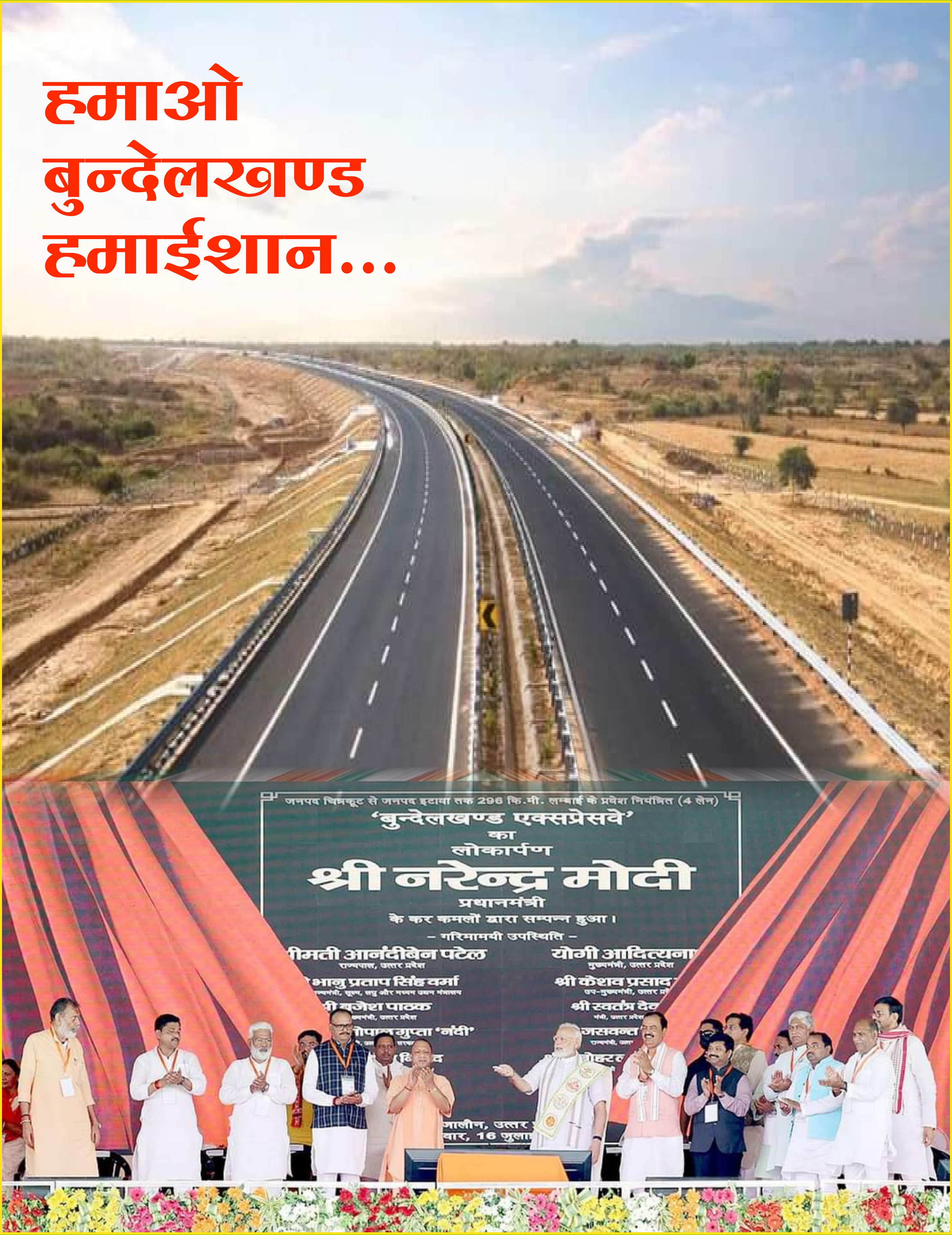

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी